आषाढ़ कृष्ण पक्ष- 7, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष- 10, अंक - 02 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल

07 जुलाई 2026 मंगलवार

आज का मौसम

33.4 अधिकतम

24.4 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

Page- 7

बात ऐसी निकली कि दूर तलक जाएगी...

राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड... मामला अब लखनऊ से दिल्ली के पाले में..!

अयोध्या में बीते महीने भर से चल रहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय और उनके करीबी माने जाने वाले ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए जाने तथा प्रशासक गोपाल राव को हटाए जाने के बाद अब आगे क्या होगा?

प्रसंगवश

■ राजेश सिरोठिया

यह सवाल बेहद मौजूं होने के साथ हर ख़ास ओ आम के मन में है। सवाल यह भी कि क्या इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो चाहते थे, वह कर चुके हैं? वैसे भी, मंदिर ट्रस्टियों में योगी का कोई खास चहेता नहीं माना जाता था। चंपत राय और अनिल मिश्रा उनके लिए लंबे समय से असहजता की वजह बताए जाते रहे हैं। अब दोनों ट्रस्ट की निर्णायक भूमिकाओं से बाहर हैं। ताजा घटनाक्रम के बाद इस पूरे बवाल में भाजपा के भीतर सुलगती आग की लपटें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंचती दिखाई दे रही हैं। अब यह लड़ाई केवल अयोध्या के चढ़ावे की नहीं रही। राजनीतिक गलियारों में इसे लखनऊ बनाम दिल्ली की जंग के रूप में भी देखा जाने लगा है।

चढ़ावा कांड के खुलासे से जुड़े पूरे घटनाक्रम की कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ लेती दिख रही है। इसके कई छुए और अनछुए पहलू हैं। योगी और चंपत राय-अनिल मिश्रा के बीच कथित खटास की कहानी भी कम रोचक नहीं है। चंपत राय बेहद साधारण जीवन जीने वाले और संघ परिवार के समर्पित कार्यकर्ता माने जाते रहे हैं। उनका मिजाज सख्त रहा है। ट्रस्ट मंडल के सदस्यों में अनिल मिश्रा उनके सबसे करीबी लोगों में गिने जाते थे। इसी तरह मंदिर कर्मचारी टिन्नू यादव पर भी उनका गहरा भरोसा बताया जाता है। चर्चाओं के मुताबिक मंदिर व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती करने वाली कंपनी के जरिए भर्ती में अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के प्रभाव की बातें सामने आती रही हैं। कहा जाता है कि शुरुआत में चंपत राय ने इस पर कोई खास ऐतराज नहीं किया। लेकिन, जब उन्हें शक हुआ कि चढ़ावे की रकम से जुड़े कुछ कर्मचारी दान की रकम में सेंधमारी कर रहे हैं, तो उन्होंने ही दान कक्ष में गुप्त कैमरे लगवाए।

बताया जाता है कि चंद दिनों की फुटेज में ही यह संकेत मिलने लगे कि हर दिन लाखों रुपये की रकम गायब हो रही है। कुछ रिपोर्टों में चोरी की रकम छह से आठ लाख रुपये प्रतिदिन तक होने का दावा किया गया है। इसके बाद घटनाक्रम को लेकर दो अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं।

पहली कहानी यह है कि चंपत राय ने पुलिस की मदद से चढ़ावा चोरी की रकम जब्त कराना शुरू किया। दूसरी कहानी यह है कि लाखों रुपये की बरामदगी के फौरन बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की। सूत्रों का दावा है कि मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा लेकिन तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। तब तक खबर हवा में तैरने लगी थी।

उधर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। इसके बाद योगी सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित कर उसे अयोध्या भेज दिया। इस एसआईटी का नेतृत्व लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। टीम में पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन भी शामिल हैं। एसआईटी ने पुलिस और प्रशासन से उपलब्ध प्रमाण जुटाए और जांच आगे बढ़ाई। जैसे-जैसे इस जांच की बातें बाहर आने लगीं, मामला मीडिया में तूल पकड़ने लगा। मीडिया के एक वर्ग ने राज्य सरकार की एसआईटी जांच की वैधानिकता और उसके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए। इसके बाद अयोध्या में पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने का रास्ता खुला।

रिपोर्ट दर्ज होते ही और बढ़ गया बवाल ...

योगी आदित्यनाथ के अयोध्या पहुंचने के बाद यह संदेश गया कि चंपत राय मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। घटनाक्रम तेजी से बदला और चंपत राय तथा अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अब ट्रस्ट ने दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। कहा जाता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपेक्षित तरजीह नहीं देते थे। अयोध्या के राजनीतिक गलियारों में एक पुराने कार्यक्रम का भी जिक्र होता है, जिसमें कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ को मंदिर परिसर के मंच से बोलने का अवसर नहीं मिला था।

यदि इन चर्चाओं में दम है तो यहीं से खटास ने अदावत का रूप लिया। इसके बाद योगी भी शायद मौके की तलाश में थे और चढ़ावा कांड ने उन्हें वह मौका दे दिया। चंपत राय पर व्यक्तिगत आर्थिक अनियमितता का आरोप आसानी से कोई स्वीकार नहीं करता। उनकी सादगी और संघ के प्रति समर्पण की चर्चा उनके विरोधी भी करते हैं। लेकिन होम्योपैथी चिकित्सक और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को लेकर अयोध्या में कई तरह की चर्चाएं हैं। उनकी पिछले पांच वर्षों की नामी-बेनामी और आय से अधिक संपत्ति की निष्पक्ष जांच हो तो तस्वीर और साफ हो सकती है। आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला जांच से ही होना चाहिए।

लेकिन असली सवाल इससे भी बड़ा है।

इस पूरे घटनाक्रम को अब लखनऊ बनाम दिल्ली की जंग के रूप में देखा जा रहा है और इसके पहले दौर में योगी आदित्यनाथ ने लंबी बढ़त बना ली है। सबसे चौंकाने वाला सवाल यह है कि दिल्ली समय रहते यह क्यों नहीं समझ सकी कि लखनऊ से एसआईटी जांच का ऐलान होते ही मामला किस दिशा में जा सकता है? यदि केंद्र को राज्य सरकार की जांच पर संदेह था तो मामला किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की पहल क्यों नहीं हुई? आर्थिक अनियमितता का मामला उत्तर प्रदेश की आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को दिया जाता तो भी बात समझ में आती। किसी उच्चस्तरीय स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाती तो भी सवाल कम उठते। यह मामला अयोध्या के किसी स्थानीय थाने के स्तर का न पहले था और न अब है।

लेकिन अब गेंद शायद दिल्ली के हाथ से निकल चुकी है। राजनीतिक मामलों के जानकारों की मानें तो अयोध्या कांड से उपजे संकट का प्रबंधन भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। यह केवल कुछ लाख या करोड़ रुपये की कथित चोरी का मामला नहीं है। यह उस जनआस्था पर लगा जख्म है, जिसे भाजपा ने बीते तीन दशकों में अपनी राजनीति के सबसे मजबूत आधार में बदला है।

अब सवाल है—इस जख्म की भरपाई कैसे होगी? यदि भाजपा इस पूरे मामले में जनता के बीच बने नैरेटिव को बदलने में नाकाम रही तो वह क्या करेगी? बैकफुट पर आई पार्टी क्या अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले फिर फ्रंट फुट पर खेलने का माद्दा जुटा पाएगी? क्या यूपी की सत्ता बचाने का पूरा जिम्मा योगी आदित्यनाथ पर छोड़ दिया जाएगा? या दिल्ली कोई बड़ा फैसला लेकर समाजवादी पार्टी के हाथ में उत्तर प्रदेश जाने से रोकने के लिए कोई नया राजनीतिक दांव चलेगी?

अयोध्या कांड अभी खत्म नहीं हुआ है।
असल में इसकी कहानी अब शुरू हुई है।

जुलाई का यह महीना कुछ और चौंकाने वाले फैसलों का गवाह बन सकता है। इस संभावना को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। क्योंकि अयोध्या में चोरी भले चढ़ावे की हुई हो, लेकिन उसकी राजनीतिक कीमत लखनऊ और दिल्ली—दोनों को चुकानी पड़ सकती है।

महाराष्ट्र के बाद एमपी की बारी... सतर्कता बरतने की अपील

अगले 72 घंटे भारी.. प्रदेश में मूसलाधार का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़ का खतरा

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश में मानसून का नया दौर और अधिक सक्रिय होने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आज से अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से पश्चिमी, मध्य और पूर्वी मध्यप्रदेश के जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर रहने की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर-पूर्वी मप्र पर बना अवदाब कमजोर होकर पूर्वी मध्यप्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है।

जिन जिलों में भारी बरसात हो सकती है उनमें इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपु,र छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी आदि शामिल हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले दिनों हुई वर्षा से जलाशयों और नदियों का जलस्तर पहले से बढ़ा हुआ है। ऐसे में आगामी 48 से 72 घंटे की तेज बारिश से कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, उफनते नालों को पार नहीं करने और मौसम संबंधी ताजा चेतावनियों पर नजर रखने की अपील की है।

नासिक में भारी बारिश के बाद सड़कों पर खड़ी कारें पानी में डूब गईं।

भोपाल-राजगढ़ वैकल्पिक मार्ग ठप

भोपाल और राजगढ़ जिले को जोड़ने वाले पार्वती नदी के अस्थायी वैकल्पिक मार्ग से गुजरने पर रोक लगा दी गई है। देर रात बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा ने यह आदेश जारी किए। नदी में जल स्तर बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया। आदेश में लिखा है कि बारिश के कारण पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तेज बहाव के कारण आवागमन अत्यंत जोखिमपूर्ण है। इसलिए आवागमन पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं।

इंदौर के पास जेतकारण गांव में सड़क धंस गई। आज ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों को उफनते नाले से सुरक्षित पार कराया।

नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर बंद

महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 300 मिमी तक बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। नासिक में बादल फटने की आशंका भी जताई है। यहां स्कूल - कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई है। वहीं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और साढ़े तीन शक्तिपीठों में शामिल सप्तश्रृंगी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आज बंद रहेंगे। रत्नागिरी जिले के शेलारवाड़ी में बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया। इसकी चपेट में आने से एक मकान का हिस्सा ढह गया। एक महिला को मलबे से सुरक्षित निकाला।

मैहर में सड़क हादसा : पूर्व एमएलए के परिवार के पांच की गई जान

मैहर, एजेंसी। मैहर-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। नादन थाना क्षेत्र के ग्राम रीघरा के पास रात करीब एक बजे हुए इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार से चल रही एक्सयूवी कार सामने चल रहे ट्रक में जा घुसी। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग किसी रिश्तेदार के यहां से जन्मदिन मनाकर वापस मैहर लौट रहे थे। सभी मृतक पूर्व विधायक स्वर्गीय लालजी पटेल के परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं।

जयपुर में ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 3 बच्चों की मौत

जयपुर। आज एक सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे गुब्बारे बेचने वाले को रौंद दिया। हादसे में दो लोग घायल भी हो गए।हादसा श्याम नगर थाना क्षेत्र के 200 फीट बाईपास पर हुआ। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने लोहे की रेलिंग तोड़ दी और सड़क किनारे नाले के पास खड़े बच्चों को कुचल दिया।

अफेयर के कारण नर्स पत्नी ने रची साजिश

पति को ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर डालकर मारा

» पहले भी छत से धक्का दिया था, लेकिन बच गया

निजामाबाद, एजेंसी

तेलंगाना में एक नर्स ने प्रेमी के साथ मिलकर 35 साल के पति की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, महिला ने 30 जून को पति को छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की थी। जब वह बच गया तो अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी नस में लगी ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर इंजेक्ट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला 32 साल की संध्या, उसके प्रेमी अनिल और उसके दोस्त वेंकट साई को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह हत्या पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी, जिसकी वजह संध्या का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था।यह पूरी घटना निजामाबाद जिले के मोपाल मंडल के न्यालाकल गांव की है। इसकी खबर सोमवार को सामने आई।

शराब पिलाकर फेंक दिया था छत से

पुलिस के मुताबिक, प्रशांत हाल ही में खाड़ी देश से लौटा था। वह किस देश में था, यह जानकारी नहीं मिली। वापस आने पर उसे संध्या के अफेयर के बारे में पता चला तो उनमें झगड़े होने लगे। 30 जून को तीनों आरोपियों ने प्रशांत को पहले खूब शराब पिलाई। फिर मारपीट कर घर की छत से नीचे धक्का दे दिया। हालांकि, गंभीर चोटों के बावजूद प्रशांत की जान बच गई। आरोपियों ने उन्हें यह कहकर अस्पताल पहुंचाया कि वह नशे की हालत में खुद गिर गए थे।

न्यूज विंडो

प्रमोशन में आरक्षण मामले की आज एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई

जबलपुर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित प्रमोशन में आरक्षण विवाद में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तस्वीर साफ हो गई है। हाई कोर्ट ने मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के समक्ष आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। आधिकारिक लिस्ट जारी होने के बाद कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के बीच चल रही सभी अटकलों पर विराम लग गया है। युगलपीठ की सूची में मामला 17 वें क्रम पर है और इसकी सुनवाई आज ही होने की संभावना है। सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद से लंबित यह मामला 17 फरवरी, 2026 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ द्वारा सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद से लंबित है।

मोदी को सर्वोच्च सम्मान

इंडोनेशिया बना ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला तीसरा देश

जकार्ता. पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस और बिजनेस से जुड़े कई अहम समझौते हुए। सबसे अहम ब्रह्मोस डील रही। इसको लेकर दोनों देशों के बीच पिछले 4 महीने से बातचीत चल रही थी। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। इसी के साथ फिलीपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय 'अस्त्र' एयर-टू-एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित करने में मदद करेगा। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया।

आज का कार्टून

मेट्रो एंकर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा - यह व्यक्तिगत गरिमा और मौलिक अधिकार का हिस्सा

कोख में बच्चा रखना है या नहीं, यह पत्नी ही करेगी फैसला, पति नहीं

इंदौर, एजेंसी

मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि कानून में निर्धारित अवधि के भीतर की गर्भावस्था पर गर्भ जारी रखना या उसका समापन करने का फैसला पूरी तरह महिला का होगा। कोर्ट ने कहा कि गर्भपात के लिए पति की सहमति आवश्यक नहीं है। इसी के साथ खंडपीठ ने 13 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट के तहत गर्भसमापन की अनुमति प्रदान कर दी।

मामला इंदौर संभाग के एक हाई प्रोफाइल दंपती से जुड़ा है, जिनका विवाह करीब दो वर्ष पहले हुआ था। विवाह के बाद दोनों के बीच लगातार विवाद बढ़ने लगे। इसी दौरान महिला गर्भवती हो गई।

गर्भावस्था लगभग 13 सप्ताह की थी, लेकिन पति-पत्नी के रिश्तों में आई खटास के कारण दोनों अलग रहने लगे। महिला का कहना था कि वैवाहिक संबंध टूटने की स्थिति में बच्चे का जन्म उसके लिए मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से कठिन होगा। भविष्य को देखते हुए उसने गर्भ जारी नहीं रखने का निर्णय लिया और अधिवक्ता जी.पी. सिंह के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पति को नोटिस जारी किया था, जिसकी विधिवत तामील भी हो गई थी, लेकिन वह किसी भी तारीख पर अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। वहीं, राज्य शासन की ओर से भी याचिका का कोई विरोध नहीं किया गया। खंडपीठ ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले एक्स बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्रत्येक महिला को अपने शरीर और प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यह उसकी व्यक्तिगत गरिमा और मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने कहा कि किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध मातृत्व स्वीकार करने या गर्भावस्था जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

विवाद और अलगाव अहम आधार

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि पति-पत्नी के संबंध गंभीर रूप से बिगड़ चुके हों, दोनों अलग रह रहे हों या तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो ऐसी परिस्थितियां महिला के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। ऐसे मामलों में महिला यदि गर्भ जारी नहीं रखना चाहती है, तो यह गर्भसमापन की अनुमति देने के लिए एक वैध और न्यायसंगत आधार हो सकता है। खंडपीठ ने संबंधित चिकित्सकों को निर्देशित किया कि गर्भसमापन की पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए की जाए। प्रक्रिया के दौरान महिला की गोपनीयता, गरिमा और सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखा जाए।

कमल के फूलों से महका मनीषा मार्केट का तालाब

भोपाल। मानसून की हरियाली के बीच भोपाल के मनीषा मार्केट स्थित तालाब का नजारा इन दिनों बेहद मनमोहक हो गया है। तालाब की सतह पर खिले गुलाबी कमल के सैकड़ों फूल प्राकृतिक सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे पाम के पेड़ और बादलों से घिरा आसमान इस दृश्य को और भी आकर्षक बना रहे हैं। सुबह और शाम के समय यहां का शांत वातावरण प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बारिश के मौसम में खिले कमल भोपाल की प्राकृतिक विरासत और जलाशयों की खूबसूरती का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

स्मार्ट ई-बस में व्हीलचेयर यूजर की लिफ्ट से होगी एंट्री

भोपाल। राजधानी में बेपटरी हो चुके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जल्द ऐसा बदलाव दिखेगा, जो अब तक सिर्फ बड़े शहरों या एयरपोर्ट जैसी आधुनिक ट्रांसपोर्ट सुविधाओं में देखने को मिलता था। शहर में आने वाली नई 25-सीटर एसी इलेक्ट्रिक बसों में ऑटोमैटिक व्हीलचेयर लिफ्ट लगाई गई हैं। इस लिफ्ट की मदद से व्हीलचेयर पर बैठे दिव्यांग यात्री बिना किसी व्यक्ति की सहायता के सीधे बस में पहुंच सकेंगे। बता दें कि अभी तक लो-फ्लोर बसों में भी व्हीलचेयर पर बैठे यात्रियों को चढ़ने-उतरने में दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन नई ई-बसों में यह व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। बस के बीच वाले गेट के पास लगी ऑटोमैटिक लिफ्ट बटन दबाते ही जमीन तक नीचे आएगी, यात्री को व्हीलचेयर सहित ऊपर उठाएगी और बस के फ्लोर तक पहुंचा देगी। पूरी प्रक्रिया में करीब 45 सेकंड लगेंगे। लिफ्ट 150 से 170 किलोग्राम तक का वजन उठा सकेगी और इसका संचालन ड्राइवर करेगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, स्मार्ट बस नई बसों को सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि स्मार्ट बस के रूप में तैयार किया गया है। यात्री बस में बैठते ही अगले स्टॉप की जानकारी ऑटोमैटिक वॉयस सिस्टम से सुन सकेंगे।

लीचेट से भूजल दूषित, दुर्गंध और धुएं से ग्रामीण परेशान

आदमपुर कचरा खंती : 7 लाख टन कचरे से 10 गांवों का पानी जहरीला, सांसों पर संकट

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

राजधानी की आदमपुर कचरा खंती, जिसे शहर के कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन के लिए तैयार किया गया था, अब आसपास के गांवों के लिए गंभीर संकट बन गई है। यहां वैज्ञानिक तरीके से कचरे के निपटारे की जगह करीब 7 लाख टन कचरे का पहाड़ खड़ा हो चुका है। इससे निकलने वाला दूषित पानी यानी लीचेट जमीन में रिसकर आसपास के क्षेत्रों के भूजल को प्रभावित कर रहा है। हरिपुरा-अर्जुन नगर, पड़रिया, शांति नगर और कोलुआ सहित करीब 10 गांवों में लोग दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई हैंडपंप, कुएं और ट्यूबवेल का पानी उपयोग लायक नहीं बचा है। नगर निगम को इन क्षेत्रों में टैंकरों और सार्वजनिक पानी की टंकियों के जरिए पेयजल उपलब्ध कराना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। दूसरी ओर, कचरे के ढेर में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं लोगों की परेशानी और बढ़ा देता है। इससे आंखों में जलन, गले में खराश, एलर्जी और सांस संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार प्रभावित भूजल को सामान्य होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। उनका कहना है कि कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण और भविष्य में बेहतर प्रबंधन ही इसका स्थायी समाधान हो सकता है। नगर निगम का कहना है कि प्रभावित गांवों में नियमित जल आपूर्ति की जा रही है और कचरे को जल्द समाप्त करने का प्रयास जारी है।

धुएं और बदबू से बढ़ रही स्वास्थ्य समस्याएं

कचरे के पहाड़ में समय-समय पर लगने वाली आग आसपास के लोगों के लिए नई परेशानी लेकर आती है। आग से निकलने वाला जहरीला धुआं कई किलोमीटर तक फैल जाता है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी होती है। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा जैसे श्वास रोगों से पीड़ित लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार दुर्गंध के कारण घरों में रहना मुश्किल हो जाता है।

विशेषज्ञ बोले- भूजल सुधार में लग सकते हैं दशकों

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि आदमपुर क्षेत्र का भूजल लंबे समय से प्रभावित है और इसे तुरंत सामान्य करना आसान नहीं होगा। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कचरे के पहाड़ को पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से हटाया भी जाए और भविष्य में बेहतर कचरा प्रबंधन किया जाए, तब भी भूजल को प्राकृतिक रूप से साफ होने में कई दशक या उससे अधिक समय लग सकता है। प्रभावित जल और दूषित वातावरण का असर खेती पर भी पड़ सकता है, जिससे यहां उगने वाले फल, सब्जियां और अनाज प्रभावित होने की आशंका रहती है।

एक शाम बशीर बद्र के नाम कार्यक्रम

आम जनता के शायर थे पद्मश्री डॉ.बशीर बद्र : घनश्याम मैथिल

भोपाल. दोपहर मेट्रो। सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना, निशातपुरा के उप मुख्य यांत्रिक अभियंता सोहन सिंह परमार ने कहा कि 'हिंदी हमारी मां है तो ऊर्दू हमारी मौसी। मशहूर शायर पद्मश्री डॉ .बशीर बद्र आम जनता के शायर थे इसलिए उनकी ग़ज़लों के शेर लोगों की जुवान पर चढ़े हुए हैं। वे मुख्य कारखाना प्रबंधक प्रफुल्ल वी. कोहाड़े के संरक्षण में 'एक शाम पद्मश्री डॉ.बशीर बद्र के नाम' कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार घनश्याम मैथिल अमृत ने मुख्य अथिति वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉ. बद्र से जुड़े संस्मरण सुनाते हुए उन्हें सहज सरल भाषा में आम आदमी का गजलकार बताया। कारखाने की सांस्कृतिक अकादमी के कलाकारों ने संगीतमय सरस्वती वंदना की मधुर प्रस्तुति दी। कारखाना के नौ रेल कवियों बी.एन. तिवारी, संत कुमार मालवीय, नीतिराज चौरे, अखिलेश लोधी, नमन चौकसे, पंकज दमाड़े, अनिल कुमार साकेत, आशीष कुमार गुप्ता एवं सुश्री जयश्री ठाकुर ने डॉ. बशीर बद्र के सम्मान में बशीर साहब की ग़ज़लों के चुनिंदा शेरों के साथ ही अपनी-अपनी रचनाओं का पाठ किया। वक्ताओं ने सभी का आव्हान करते हुए कहा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी मान्याता प्राप्त 22 भाषाएं हमारी अपनी हैं, वे सभी अपने-अपने राज्य की राजभाषाएं हैं। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का ही प्रयोग करें। इस अवसर पर अक्षय गंगरवाल, कार्य प्रबंधक (यांत्रिक), शिवम असाटी, कार्य प्रबंधक (विद्युत), आशीष कुमार झारिया, कार्य प्रबंधक, आर.के. उपाध्याय, एसीएमटी एवं रमेश कुमार रंगा, सहायक सामग्री प्रबंधक सहित बड़ी संख्या में कारखाना के कर्मचारी उपस्थित रहे। संचालन ग़ज़लकार एवं गीतकार बी.एन.तिवारी ने किया।

मासूम से दरिंदगी करने वाले मुंहबोले 'चाचू' को 7 साल की सजा, लगा 50 हजार का जुर्माना

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

राजधानी भोपाल की एक विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और लैंगिक हमले के एक संगीन मामले में आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) व 15वें अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने अपने फैसले में आरोपी राहुल श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए उसे अधिकतम दंड से दंडित किया है। साथ ही, अदालत ने पीड़िता को 50 हजार रुपये का प्रतिकर (मुआवजा) दिए जाने का भी आदेश दिया है। मामला 25 जून 2025 का है, जब पीड़िता ने अपनी दादी और बुआ के साथ थाना हबीबगंज में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी राहुल श्रीवास्तव उसके पिता का बचपन का दोस्त था, इसलिए उसका घर पर आना-जाना लगा रहता था और वह उसे 'चाचू' कहकर बुलाती थी। 22 जून 2025 की रात करीब 11 बजे, आरोपित शराब के नशे में पीड़िता के घर आया था। इस दौरान उसने अकेले पाकर बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं और उसका शारीरिक उत्पीड़न किया। पीड़िता के विरोध करने पर वह वहां से भाग निकली। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अदालत में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और नवीन श्रीवास्तव ने मामले की पैरवी की। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों, तर्कों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने राहुल श्रीवास्तव को दोषी पाया।

पं. खुशीलाल अस्पताल परिसर को मिलेगा नया स्वरूप

भोपाल। राजधानी के पंडित खुशीलाल शर्मा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर को आधुनिक सुविधाओं से विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। कमिश्नर कर्मवीर शर्मा ने बैठक में कॉलेज भवन, गर्ल्स हॉस्टल, ऑडिटोरियम और हर्बल गार्डन को जोड़ने के लिए पाथ-वे और ब्रिज निर्माण की विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के तहत अस्पताल और पीजी भवनों की मरम्मत, लैब्स का आधुनिकीकरण और डिजिटल सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। मरीजों और छात्रों की सुविधा के लिए डिजिटल एक्स-रे मशीन, अग्निशमन उपकरण और सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है।

लड़की ने ठुकराया प्रेम प्रस्ताव तो 19 वर्षीय स्टूडेंट ने फांसी लगाकर दी जान

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

कमलानगर थाना क्षेत्र स्थित शबरी नगर में एक 19 वर्षीय कालेज छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र अपनी महिला मित्र द्वारा प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने से मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, शबरी नगर निवासी अनुराग (19) छात्र था। उसकी शहडोल निवासी एक युवती से दोस्ती थी और वह उसे पसंद करता था। कुछ दिन पहले अनुराग ने युवती के सामने अपने प्रेम का इजहार किया था, लेकिन युवती ने प्रस्ताव स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद से वह काफी निराश रहने लगा था। स्वजनों ने उसकी बदली हुई मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसका तनाव कम नहीं हुआ। सोमवार करीब दो बजे स्वजन ने उसे घर में फांसी के फंदे पर लटका देखा। तत्काल उसे नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच जारी है।

मेट्रो एंकर हमीदिया अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी को दिया सफल अंजाम, मां और नवजात दोनों स्वस्थ

एक ही ऑपरेशन में सुरक्षित प्रसव, 10.2 किलो का ट्यूमर भी निकाला

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

राजधानी के हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बार फिर जटिल चिकित्सा चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा कर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की उत्कृष्टता साबित की है।

विशेषज्ञों की टीम ने एक ही ऑपरेशन में पहले 2.6 किलोग्राम के स्वस्थ शिशु का सुरक्षित प्रसव कराया और तुरंत बाद महिला की ओवरी से 10.2 किलोग्राम का विशाल ट्यूमर निकालकर उसकी जान बचाई।

ऑपरेशन के बाद मां और नवजात दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं।

डॉक्टरों के अनुसार गर्भावस्था के दौरान ओवरी में इतना बड़ा ट्यूमर होना अत्यंत दुर्लभ और जोखिमभरा माना जाता है। इस स्थिति में मां और गर्भस्थ शिशु दोनों की जान को खतरा रहता है। ट्यूमर का आकार, संभावित रक्तस्राव और गर्भाशय की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों ने पहले से विस्तृत सर्जिकल योजना तैयार की, जिससे प्रसव और ट्यूमर निकालने की दोनों प्रक्रियाएं सुरक्षित तरीके से पूरी की जा सकीं।

इस जटिल सर्जरी का नेतृत्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. पल्लवी सिंह और डॉ. अदिति खरे ने किया। एनेस्थीसिया और सर्जिकल विशेषज्ञों की टीम पूरे ऑपरेशन के दौरान मौजूद रही। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. कविता सिंह और विभागाध्यक्ष डॉ. रेखा वाधवानी ने बताया कि गर्भावस्था में इतने बड़े ओवरी ट्यूमर के मामले बेहद कम देखने को मिलते हैं। ऐसे ऑपरेशन में रक्तस्राव, ट्यूमर फटने और आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है, लेकिन विशेषज्ञों के बेहतर समन्वय और सटीक योजना से यह चुनौतीपूर्ण सर्जरी सफल रही।

ट्यूमर फटने की थी आशंका

गर्भावस्था के दौरान ओवरी में 10.2 किलोग्राम का ट्यूमर होना अत्यंत दुर्लभ स्थिति है। ऐसे मामलों में ट्यूमर का बढ़ता आकार गर्भस्थ शिशु और मां, दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव, ट्यूमर फटने और आसपास के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचने का जोखिम रहता है। इसलिए डॉक्टरों ने पहले सुरक्षित प्रसव कराया और फिर अत्यंत सावधानी के साथ ट्यूमर को निकाला। पूरी प्रक्रिया में स्त्री रोग, एनेस्थीसिया और सर्जिकल विशेषज्ञों के समन्वय ने सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अस्पताल की बड़ी उपलब्धि

हमीदिया अस्पताल की यह सफलता सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषज्ञता और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का उदाहरण है। जटिल और उच्च जोखिम वाले इस ऑपरेशन को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सुनियोजित रणनीति के साथ अंजाम दिया। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. कविता सिंह और विभागाध्यक्ष डॉ. रेखा वाधवानी ने बताया कि ऐसे मामले चिकित्सा विज्ञान में बेहद दुर्लभ होते हैं। सफल सर्जरी ने यह साबित किया कि सरकारी अस्पतालों में भी गंभीर और जटिल मामलों का विश्वस्तरीय उपचार संभव है, जिससे मरीजों का भरोसा और मजबूत हुआ है।

निवेश के नाम पर व्यक्ति से 2 लाख की साइबर ठगी

भोपाल। राजधानी के बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर एक व्यक्ति से करीब दो लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। वैष्णो परिसर निवासी 47 वर्षीय सत्यपाल सिंह से ठगों ने खुद को ट्रेड नोवा लाइट कंपनी से जुड़ा बताकर संपर्क किया। आरोपितों ने पहले 10 हजार रुपए के निवेश पर 9,800 रुपए का रिटर्न देकर भरोसा जीता। इसके बाद बोनस और बड़े मुनाफे का लालच देकर उनसे अलग-अलग किस्तों में करीब दो लाख रुपए जमा करा लिए। रकम वापस मांगने पर आरोपितों ने संपर्क बंद कर दिया। पुलिस ने अज्ञात जालसाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मध्यप्रदेश को फिश एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी

कुवैत से आया 7,430 करोड़ का मत्स्य निवेश सीएम मोहन की मौजूदगी में एग्रीमेंट साइन

चार बड़े जलाशयों में होगा आधुनिक केज कल्चर

35 हजार रोजगार और 6 हजार करोड़ के निर्यात का लक्ष्य

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में सोमवार को कुवैत की अग्रणी कंपनी ज़बेदी अल-कुवैत फिशरीज कंपनी और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपए के निवेश और बाय-बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में हुए इस समझौते को प्रदेश के मत्स्य उद्योग और मछुआ समुदाय के लिए ऐतिहासिक बताया गया। यह निवेश मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत किया जाएगा, जिससे प्रदेश को देश के प्रमुख मत्स्य उत्पादन और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

मत्स्य पालन से बढ़ेगी किसानों और मछुआरों की आय- मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सरकार किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में उपलब्ध विशाल जल संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग कर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मछुआरा समुदाय की आजीविका मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुवैत जैसे मित्र देश के साथ हुआ यह समझौता प्रदेश के मत्स्य क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा।

चार जलाशयों में विकसित होगा आधुनिक इंफास्ट्रक्चर

समझौते के तहत इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशयों में आधुनिक केज कल्चर प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जिससे उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग और निर्यात तक की पूरी व्यवस्था मजबूत होगी। इस परियोजना के जरिए प्रदेश में लगभग 4 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होने का अनुमान है। इससे मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रदेश की हिस्सेदारी राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूत होगी।

एक्वापोनिक्स और ग्रीन हाउस से होगा सब्जियों का उत्पादन

मत्स्य परियोजना केवल मछली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी। इसके साथ एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीन हाउस तकनीक का उपयोग करते हुए लगभग 1.23 लाख टन सब्जियों का उत्पादन भी किया जाएगा। आधुनिक कृषि और मत्स्य पालन के इस एकीकृत मॉडल से किसानों को अतिरिक्त आय के नए अवसर मिलेंगे। इससे जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रणाली विकसित होगी।

35 हजार रोजगार और 6 हजार करोड़ के निर्यात का लक्ष्य

परियोजना से प्रदेश में 15 हजार प्रत्यक्ष और 20 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। सरकार ने इस निवेश के माध्यम से लगभग 6 हजार करोड़ रुपए के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य तय किया है। इससे प्रदेश के मछुआरों, युवाओं और मत्स्य उद्योग से जुड़े उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा। ज़बेदी अल-कुवैत फिशरीज कंपनी का 10 से अधिक देशों में प्रीमियम खाद्य उत्पादों का मजबूत नेटवर्क है, जिसका लाभ मध्यप्रदेश के मत्स्य उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह समझौता प्रदेश को देश का अग्रणी मत्स्य निवेश और निर्यात केंद्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

विधायकों से जुड़े सरकारी टीचर्स की स्कूलों में वापसी

विधानसभा के मानसून सत्र से पहले 213 शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म, रिलीविंग के आदेश जारी

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले स्कूलों से बाहर काम कर रहे 213 सरकारी शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 16 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को सभी शिक्षकों को तत्काल उनके मूल पदस्थापना स्थल यानी स्कूलों में वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई पिछले साल 30 जुलाई को विधानसभा में सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा के सवाल के आधार पर हुई जिला स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है।

शिक्षा विभाग की सूची के अनुसार कई शिक्षक विधायक कार्यालयों में निजी सहायक (पीए) के रूप में और कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, निर्वाचन कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जनपद पंचायत, एसडीएम कार्यालय और अन्य प्रशासनिक दफ्तरों में सालों से अटैच होकर काम कर रहे थे। अब सभी को मूल स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने के लिए रिलीव करने के आदेश जारी किए गए हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय की समीक्षा में उज्जैन, देवास, नीमच, शहडोल, दतिया, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, गुना, रीवा, सीधी, कटनी, सिंगरौली, सतना, राजगढ़ और मंडला सहित 16 जिलों के 213 शिक्षकों के संलग्नीकरण का विवरण सामने आया। विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी को उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजा जाए, ताकि स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो।

विधानसभा में सवाल के बाद हुई कार्रवाई

पिछले विधानसभा सत्र में स्कूलों से बाहर संलग्न शिक्षकों का मुद्दा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1108 के माध्यम से उठाया गया था। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों से जानकारी मंगाई। मानसून सत्र शुरू होने से पहले संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संलग्नीकरण समाप्त कर संबंधित शिक्षकों को मूल पदस्थापना वाले विद्यालयों में वापस भेजने के निर्देश दिए हैं।

मंत्रालय में लगी सहायक शिक्षक की ड्यूटी

भोपाल के शासकीय प्राथमिक शाला बांसखेडी के सहायक शिक्षक मनीष शर्मा 2015 से मंत्रालय भोपाल में अटैच हैं। भोपाल के शासकीय माध्यमिक शाला छोला के सहायक शिक्षक सुनील धानोरकर 2008 से मंत्रालय में अटैच हैं। भोपाल के शासकीय प्राथमिक पाठशाला परवलिया की प्राथमिक शिक्षिका प्रियंका शर्मा अगस्त 2023 से विमुक्त जाति आश्रम इब्राहिमपुरा, बैरसिया में अटैच हैं। जबलपुर के शासकीय माध्यमिक शाला उमरिया पठरा के सहायक शिक्षक सुभाग सिंह पटेल बहोरीबंद विधायक के निज सचिव के तौर पर अगस्त 2024 से अटैच हैं। नरसिंहपुर के करेली हायर सेकेण्डरी स्कूल के लेक्चरर आनंद कुमार श्रीवास्तव तेंदूखेड़ा विधायक के यहां अगस्त 2024 से अटैच हैं।

समाज कल्याण योजनाओं के एक लाख आवेदन लंबित

भोपाल। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विभिन्न योजनाओं के एक लाख से अधिक आवेदन लंबित होने पर विभाग ने गंभीर चिंता जताई है। सामाजिक न्याय आयुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी ने संभागीय और जिला अधिकारियों को परिपत्र जारी कर स्पष्ट कहा है कि समय पर निराकरण नहीं होने से न केवल पात्र हितग्राहियों को परेशानी हो रही है, बल्कि सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है। आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी प्रतिदिन संबंधित पोर्टलों पर लॉग-इन कर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करें और उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें।

पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा लाभ

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न योजनाओं के 1,00,436 आवेदन लंबित हैं। वहीं, पिछले छह माह से 1.48 लाख पेंशन भुगतान प्रकरण असफल पड़े हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के 44,666 पात्र हितग्राहियों को अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। इसके अलावा स्पर्श पोर्टल पर 3.68 लाख दिव्यांगजनों की यूडीआईडी मैपिंग लंबित है। मुख्यमंत्री कल्याण (विधवा) विवाह योजना के 420 आवेदन, पेंशन पोर्टल पर 15 दिन से अधिक समय से 11,863 आवेदन तथा 6,062 डिजिटल साइन वाले प्रकरण भी लंबित हैं। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि अनावश्यक जांच या अन्य कारणों से आवेदन लंबित रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी।

मात्र 10 हजार वोट इधर-उधर होने से बदल जाते हैं नतीजे

दतिया उप चुनाव पर नजर... हर बार होता गया है यहां कांटे का मुकाबला

भोपाल, दोपहर मेट्रो

दतिया विधानसभा का चुनावी इतिहास बताता है कि पिछले 15 वर्षों में यहां राजनीतिक मुकाबले का स्वरूप लगातार बदला है। वर्ष 2008 से 2018 तक भाजपा ने लगातार तीन चुनाव जीते, लेकिन 2023 में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर इस क्रम को तोड़ दिया। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला हर चुनाव में और अधिक कड़ा होता गया।

पिछले चार विधानसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो 2008 से 2018 तक भाजपा ने लगातार तीन बार जीत दर्ज की। हालांकि, हर चुनाव के साथ कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता गया। 2018 में मुकाबला बेहद कांटे का रहा और 2023 में कांग्रेस ने भाजपा का 15 साल पुराना विजय अभियान रोक दिया। यही वजह है कि इस बार उपचुनाव में भी दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर की संभावना जताई जा रही है।

2008-भाजपा को मिली बढ़त, बसपा रही दूसरे स्थान पर- 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने 34,489 वोट (34.10 फीसदी) हासिल कर जीत दर्ज की। उस समय बसपा मुख्य प्रतिद्वंद्वी रही। बसपा के राजेंद्र भारती को 23,256 वोट (22.99 फीसदी), जबकि कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 19,209 वोट (18.99त्न) मिले। भाजपा ने यह चुनाव 11,233 वोटों के अंतर से जीता।

2013: कांग्रेस ने बढ़ाई चुनौती

2013 में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमट गया। भाजपा उम्मीदवार डॉ. नरोत्तम मिश्रा को 57,438 वोट (44.16 फीसदी) मिले, जबकि कांग्रेस के राजेंद्र भारती को 45,357 वोट (34.87 फीसदी) प्राप्त हुए। बसपा के कालीचरण कुशवाह को 20,191 वोट (15.52 फीसदी) मिले। भाजपा ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करते हुए 12,081 वोटों की बढ़त बनाई।

2018:जीत का अंतर सिमटा

2018 का चुनाव बेहद करीबी रहा। भाजपा के डॉ. नरोत्तम मिश्रा को 72,209 वोट (49 फीसदी) मिले, जबकि कांग्रेस के राजेंद्र भारती को 69,553 वोट (47.2त्न) मिले। दोनों के बीच जीत का अंतर केवल 2,656 वोट रहा। इससे स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी।

2023: बदला चुनावी समीकरण

2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा का लगातार तीन चुनावों का विजय अभियान रोक दिया। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने भाजपा के डॉ. नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से पराजित किया। इस परिणाम के साथ दतिया विधानसभा में 15 साल बाद सत्ता का समीकरण बदल गया।

उपचुनाव में क्यों अहम है 10 हजार वोट?

पिछले चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि दतिया में जीत-हार का अंतर कभी 12 हजार वोट रहा तो कभी सिर्फ 2,656 वोट। 2023 में कांग्रेस ने 7,742 वोटों से जीत दर्ज की। ऐसे में यदि करीब 10 हजार मतदाताओं का रुझान किसी एक दल की ओर बदलता है तो पूरा चुनावी परिणाम बदल सकता है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की नजरें उन क्षेत्रों पर हैं, जहां पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत-हार हुई थी।

आनन-फानन में करा दिया अधूरी पुलिया का उद्घाटन

लोकार्पण के 24 घंटे में बह गई 3.93 करोड़ की सड़क, गुणवत्ता पर उठे सवाल

सिवनी, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में करोड़ों रुपए से निर्मित पुलिया का लोकार्पण के 24 घंटे बाद ही ढहने का मामला सामने आया है। पुलिया ढहने के बाद निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि निर्माणाधीन पुलिया का लोकार्पण आनन-फानन में करा दिया गया। वहीं पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे है।

सिवनी में करोड़ों की लागत से बन रही सड़क पहली ही बारिश में बह गई।

केवलारी विकासखंड के मोहबर्रा-सारसडोल मार्ग पर बनी पुलिया और सड़क का हिस्सा धंसने से निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 3 करोड़ 93 लाख रुपये की लागत से बने इस मार्ग का लोकार्पण 1 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने धान महोत्सव के दौरान किया था। 2 जुलाई की पहली बारिश में पुलिया और डामरीकृत सड़क का हिस्सा बह गया। इस घटना ने एक और गम्भीर लापरवाही को उजागर कर दिया है।

30 जून तक पंचायतों में रिक्त हुए पदों की जानकारी 13 जुलाई तक भेजें

भोपाल। सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग दिनेश श्रीवास्तव ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 30 जून, 2026 तक विभिन्न पंचायतों में आकस्मिक रूप से रिक्त पदों की ऑनलाइन जानकारी 13 जुलाई तक प्रमाणीकरण सहित उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा है कि इसी जानकारी के आधार पर पंचायतों के रिक्त पदों के लिये उप निर्वाचन करवाये जायेंगे। ऑनलाइन जानकारी भेजने में कोई कठिनाई हो तो राज्य निर्वाचन आयोग की आईटी शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

राज्यसभा चुनाव पर तकरार बरकरार

HC का रुख करेंगी मीनाक्षी बोलीं- भाजपा ने रची साजिश

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में समझौता (कॉम्प्रोमाइज) हुआ है और कांग्रेस इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में चुनाव याचिका (इलेक्शन पिटिशन) दायर करेगी। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि पार्टी की लीगल टीम इस मामले पर काम कर रही है और परिणाम घोषित होने के 45 दिन के भीतर याचिका दायर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, ना तो नामांकन पत्र

में कोई गलती थी और ना ही हमारे किसी साथी से कोई चूक हुई। जब फार्म-16 में नोटिस के उल्लेख का कोई कॉलम ही नहीं है, तो उसके आधार पर नामांकन निरस्त करना यह साबित करता है कि यह एक षड्यंत्र था। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को हर स्तर पर लड़ेगी, क्योंकि यह मामला केवल एक सीट का नहीं, बल्कि पूरी चुनाव व्यवस्था की निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है।

शासकीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई तक

भोपाल, दोपहर मेट्रो

राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग ने संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक/बालिका शासकीय छात्रावासों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए अंतिम चरण में 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। इसके लिए विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से विशेष होस्टल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है।

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि, प्रदेश में संचालित छात्रावासों में विशेष रूप से वंचित वर्गों की बालिका/बालक को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शी ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली प्रारंभ की गई है। यह ई-हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली एक समेकित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया, सीट आवंटन, अभिलेख संधारण तथा प्रशासनिक कार्यों को ऑनलाइन एवं पारदर्शिता के साथ संचालित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह प्रणाली विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप-I एवं III एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास बालक/बालिका छात्रावासों के पारदर्शी प्रबंधन एवं उनमें प्रवेश की सुविधा के लिए विकसित की गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार छात्रावासों में कक्षा 6वीं एवं अन्य कक्षाओं की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी अंतिम चरण में 20 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

डिजिटल जंग में बड़ी पहल | **उज्जैन बनेगा पहला ग्रीन कुंभ मॉडल**

हरियाली की छांव में होगा सिंहस्थ, 114 किमी का बनेगा हरित कॉरिडोर

3 लाख से ज्यादा गड्ढों की खुदाई पूरी, पौधों की होगी जियो-टैगिंग

उज्जैन, दोपहर मेट्रो

पहली बार उज्जैन में 2028 में होने वाला सिंहस्थ कुंभ पर्यावरण की प्राथमिकताओं के साथ होगा। ग्रीन कुंभ में 10 लाख पौधों से हरित कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। ग्रीन कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। तीन लाख से अधिक गड्ढों की खुदाई पूरी कर ली गई है। योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिंहस्थ क्षेत्र की 114 किलोमीटर लंबी सड़कों को हरित कॉरिडोर में बदलना है। इन मार्गों के दोनों ओर 84 हजार बड़े और छायादार पौधे लगाए जाएंगे।

इनमें मुख्य रूप से नीम, करंज, जामुन और अन्य छायादार प्रजातियों के 10 से 12 फीट ऊंचे पौधे लगाए जाएंगे। इन प्रजातियों का चयन इसलिए किया गया है कि ये कम समय में अच्छी वृद्धि कर सकें और सिंहस्थ-2028 तक श्रद्धालुओं को प्राकृतिक छाया उपलब्ध करा सकें। बढ़ते तापमान और हीटवेव को देखते हुए यह चयन केवल सुंदरीकरण के लिए नहीं, बल्कि जलवायु अनुकूल अधोसंरचना विकसित करने की रणनीति का हिस्सा है। प्रशासन निर्माणाधीन 29 किलोमीटर लंबे घाटों और मार्गों के किनारे भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण करेगा। इसके अलावा शहर के 400 से अधिक उद्यान, प्रमुख जलाशयों के किनारे, शासकीय परिसरों और संस्थागत क्षेत्रों को भी इस हरित अभियान से जोड़ा गया है।

3 लाख से ज्यादा गड्ढों की खुदाई पूरी

- 10 से 12 फीट ऊंचे होंगे लगाए जाने वाले पौधे
- 29 किमी निर्माणाधीन घाट और मार्गों पर भी पौधारोपण होगा
- 400 से ज्यादा उद्यान भी हरित अभियान से जुड़ेंगे

सनातन परंपरा और प्रकृति संरक्षण का सामूहिक संकल्प

पौधों की जियो-टैगिंग की जाएगी, ताकि संरक्षण और जीवित रहने की भी लगातार निगरानी की जा सके। सनातन परंपरा में पीपल, बरगद, नीम और बेल जैसे पेड़ों को देवतुल्य माना गया है। पुराणों में पौधारोपण को यज्ञ और पुण्य का कार्य बताया गया है। ऐसे में सिंहस्थ-2028 के लिए 10 लाख पौधों का अभियान केवल हरियाली बढ़ाने की योजना नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति संरक्षण और भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण का सामूहिक संकल्प भी है।

जनादेश का सौदा

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतपेटी नहीं, बल्कि मतदाता का विश्वास होता है। चुनाव के दिन डाला गया एक वोट केवल किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं पड़ता, बल्कि एक विचार, एक दल और एक राजनीतिक वादे के समर्थन में भी दर्ज होता है। इसलिए जब चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद वही जनप्रतिनिधि अपनी राजनीतिक निष्ठा बदल लेता है, तब प्रश्न केवल दल-बदल का नहीं रहता, बल्कि जनादेश की गरिमा का बन जाता है। पश्चिम बंगाल में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बार फिर दल-बदल विरोधी कानून की कमजोरियों को सामने ला खड़ा किया है। दो-तिहाई से अधिक विधायकों और सांसदों के दल बदलने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि कानून इसे किस दृष्टि से देखता है। कहीं अलग समूह बनाकर अयोग्यता से बचने की कोशिश हो रही है, तो कहीं किसी नए दल में विलय का रास्ता अपनाया गया है। कानूनी बहस अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र का मूल प्रश्न उससे कहीं बड़ा है-जिस जनादेश के सहारे सत्ता तक पहुंचा गया, क्या उसे इतनी आसानी से बदला जा सकता है? दल-बदल विरोधी कानून चार दशक पहले राजनीतिक अस्थिरता रोकने के लिए बनाया गया था। उस समय इसकी सबसे बड़ी चुनौती सत्ता के लिए होने वाली खरीद-फरोख्त थी। आज राजनीति बदल चुकी है, लेकिन कानून की कई परिभाषाएं अब भी धुंधली हैं। 'पार्टी में विभाजन' का अर्थ क्या है? क्या केवल निर्वाचित सदस्यों का समूह ही पार्टी है, या संगठन भी उसकी आत्मा है? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर न होने से हर बड़े दल- बदल के बाद विवाद खड़ा हो जाता है और फैसले भी परिस्थितियों के अनुसार बदलते दिखाई देते हैं। इस पूरे विवाद का सबसे मौन लेकिन सबसे बड़ा पक्ष मतदाता है। उसने जिस दल की नीतियों और विचारधारा पर भरोसा करके वोट दिया था, उसका प्रतिनिधि यदि कुछ दिनों बाद विरोधी खेमे में दिखाई दे, तो यह केवल राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता की परीक्षा है। जनता अपने प्रतिनिधि को पांच वर्षों के लिए अधिकार देती है, लेकिन उस अधिकार का आधार वही जनादेश होता है, जिसे बीच रास्ते में बदला नहीं जा सकता। अब समय आ गया है कि दल- बदल विरोधी कानून को केवल विधायकों और सांसदों की सुविधा के नजरिए से नहीं, बल्कि मतदाता के अधिकारों के दृष्टिकोण से देखा जाए।

भारत की शिक्षा परंपरा और गैर-शैक्षणिक दायित्वों के बोझ तले शिक्षा व्यवस्था

प्रो. एस.के. सिंह
प्राध्यापक

किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा न केवल मनुष्यों के निर्माण का आधार है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतिबिंब भी होती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शिक्षा राष्ट्र की आत्मा होती है। भारत की शिक्षा परंपरा सदियों तक विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्र केवल ज्ञान के ही नहीं, बल्कि वैश्विक बौद्धिक विमर्श के भी प्रमुख केंद्र थे, जहाँ दुनिया के विभिन्न देशों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे, क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने हमेशा ज्ञान, नैतिकता, चरित्र-निर्माण तथा मानव एवं विश्व-कल्याण के आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है, लेकिन मध्यकाल और विशेषकर औपनिवेशिक काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर गंभीर आघात पहुंचाया गया।

भारतीय ज्ञान-परंपरा को हानि पहुँचाने के लिए अनेक पारंपरिक शिक्षण संस्थानों को नष्ट किया गया। औपनिवेशिक शासन ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित की, जिसमें भारतीय भाषाओं एवं भारतीय ज्ञान-संपदा को कमतर आँकते हुए अंग्रेज़ी-केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। औपनिवेशिक काल में भारतीय ज्ञान-परंपरा, गुरुकुल व्यवस्था तथा स्वदेशी शिक्षण संस्थानों को जिस सुनियोजित तरीके से कमजोर किया गया, वैसा उदाहरण भारतीय इतिहास के अनेक पूर्ववर्ती कालखंडों में दिखाई नहीं देता। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के विस्तार के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या तो बढ़ी, विभिन्न आयोग भी गठित किए गए, लेकिन शिक्षा के भारतीयकरण, मातृभाषा में शिक्षण एवं भारतीय ज्ञान-परंपरा के पुनर्स्थापन जैसे विषयों पर ठोस और व्यापक परिवर्तन लंबे समय तक दिखाई नहीं दिया। तत्कालीन सरकारें शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित बुनियादी परिवर्तन करने का साहस ही नहीं जुटा सकीं। परिणामस्वरूप, शिक्षा व्यवस्था काफी हद तक उसी ढाँचे में चलती रही, जिसकी नींव औपनिवेशिक काल में रखी गई थी। ऐसे परिदृश्य में स्वतंत्रता के लगभग 73 वर्ष बाद, 2020 में एनईपी 2020 के माध्यम से देश को एक बेहद लचीली, समावेशी, बहुलतावादी, प्रगतिशील, छात्र-केंद्रित एवं भारतीयता से ओत-प्रोत शिक्षा नीति मिली, जिसमें भारतीय ज्ञान-परंपरा और मातृभाषा को केंद्र में रखते हुए छात्रों के सर्वांगीण विकास तथा उन्हें जीवन के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी नीति में शिक्षा को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की ठोस पहल की गई है। इसलिए इसे सही मायनों में स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय शिक्षा नीति कहा जा सकता है। लेकिन शिक्षकों पर प्रशासनिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्यों का बढ़ता बोझ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उसके अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा नजर आ रहा है। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि सांदीपनि और आचार्य चाणक्य जैसे शिक्षकों की परंपरा इसलिए महान नहीं बनी कि वे प्रशासनिक औपचारिकताओं में दक्ष थे, बल्कि इसलिए बनी कि वे अपने शिष्यों के व्यक्तित्व-निर्माण में पूर्णतः समर्पित थे। उनके आश्रमों में शिक्षा का केंद्र-बिंदु गुरु और शिष्य का जीवंत संवाद था, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षकों की गैर-शैक्षणिक कार्यों में बढ़ती व्यस्तता के कारण यह संवाद निरंतर कम होता जा रहा है, जिससे शिक्षण एवं शोध की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा मंडराने लगा है। निरंतर रिपोर्टिंग, पोर्टल प्रबंधन, डेटा अपलोडिंग, निर्वाचन एवं जनगणना संबंधी कार्य, विभिन्न सरकारी सर्वेक्षण, छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन, आधार लिंकिंग, मध्यान्ह भोजन योजना का प्रबंधन, बार-बार माँगी जाने वाली सूचनाओं का संकलन, संस्थान स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन एवं संचालन, विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रमों में व्यस्तता तथा अनेक गैर-शैक्षणिक दायित्वों के कारण शिक्षकों को अपने मूल दायित्व शिक्षण, अध्ययन एवं शोध के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।

शिक्षक का कार्य केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं होता; उसके अध्यापन की गुणवत्ता उसके सतत अध्ययन, चिंतन, मनन और आत्मविकास पर निर्भर करती है। इसलिए शिक्षक चौबीसों घंटे अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। जो लोग यह मानते हैं कि शिक्षण कार्य समाप्त होते ही शिक्षक अपने दायित्वों से मुक्त होकर पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है, वे शिक्षक के वास्तविक उत्तरदायित्व, उसकी भूमिका की प्रकृति तथा शिक्षा की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को भली-भाँति नहीं समझते और इसी भ्रांति के कारण शिक्षक पर गैर-शैक्षणिक दायित्वों का अनावश्यक बोझ लादने का समर्थन करते हैं।

मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसी अनेक नीतियां एवं योजनाएं रही हैं, जिनकी मूल भावना अत्यंत श्रेष्ठ एवं पवित्र रही है, लेकिन उनकी सफलता और अपेक्षित परिणाम काफी हद तक उनके क्रियान्वयन पर निर्भर रहे हैं। देश में 2016 में लागू की गई नोटबंदी इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। नोटबंदी का निर्णय मूलतः काले धन, नकली मुद्रा तथा अवैध आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया एक दूरदर्शी और साहसिक कदम था।

नोटबंदी के पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा को लेकर न तब कोई संदेह था और न आज है, लेकिन क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हुई कुछ व्यावहारिक चुनौतियों एवं कठिनाइयों के कारण नोटबंदी से वे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके, जिनकी आशा की गई थी। नोटबंदी सरकार का ऐसा निर्णय था, जिसने वैश्विक स्तर पर यह धारणा स्थापित की कि भारत में ऐसा नेतृत्व उभर चुका है, जो केवल लोकप्रिय निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित में आवश्यक होने पर कठोर, अप्रिय और चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने से भी नहीं हिचकेगा। नोटबंदी की सराहना नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर ने भी की थी।

भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक इस बात पर सभी सहमत हैं कि शिक्षा में वास्तविक और बुनियादी बदलाव केवल शिक्षकों के माध्यम से ही संभव है। यदि हमें एनईपी 2020 के वास्तविक लक्ष्यों तक पहुंचना है, तो हमें शिक्षक को गैर-शैक्षणिक कार्यों के बोझ से मुक्त कर उसके वास्तविक दायित्व शिक्षण, शोध एवं अधिगम पर केंद्रित होने का अवसर देना होगा। अन्यथा एक उत्कृष्ट और दूरदर्शी शिक्षा नीति भी क्रियान्वयन की कमजोरियों के कारण अपने अपेक्षित परिणामों से वंचित रह सकती है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

बढ़ती जनसंख्या... अब दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा या नई शासन प्रणाली जरूरी

मनोज कुमार मिश्र
स्तंभकार

दिल्ली की जनगणना के आरंभिक जानकारी के मुताबिक दिल्ली की आबादी दो करोड़ तीस लाख से ज्यादा हो गई है। माना जा रहा है कि यह आंकड़ा ढाई करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की आबादी इतनी ही और होगी, जिसे दिल्ली की ही विस्तारित आबादी माना जाता है। तमाम प्रयास के बावजूद एनसीआर प्लानिंग बोर्ड दिल्ली पर से आबादी का बोझ घटा नहीं पाया। इसके ठीक उलट एनसीआर की आबादी भी रोजगार, व्यवसाय से ले लेकर उपचार आदि हर काम के लिए दिल्ली पर ही निर्भर है। अभी संयोग से दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार से लेकर केन्द्र में भी भाजपा की अगुवाई वाली सरकार है। बावजूद इसके दिल्ली में किसी सरकार के पास पूरे अधिकार नहीं हैं। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली आज भी बहुशासन प्रणाली की दंश झेल रही है।

जिस भाजपा के अभियान ने दिल्ली को वापस विधानसभा दिलवाई और नई व्यवस्था के तहत 1993 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में जीत कर सरकार बनाई, उसी भाजपा के 2025 के विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में पहली बार दिल्ली को पूरा (पूर्ण) राज्य बनाने के सवाल पर चुप्पी दिखी। 1483 वर्ग किलोमीटर की दिल्ली में आबादी समाने की एक सीमा है। वह भी तब जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास काम करने के पूरे अधिकार न हों। जो अधिकार दिल्ली के उप राज्यपाल के पास हैं कायदे में वही अधिकार दिल्ली सरकार के पास होने चाहिए। इसके अलावा पूरे एनसीआर के लिए नई शासन व्यवस्था पर भी प्राथमिकता से बात होनी चाहिए। दिल्ली की बहुशासन प्रणाली की परेशानियों को समझने का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता है। सालों से दिल्ली में रह रहे एक अध्यापक ने सवाल किया कि दिल्ली के एक जनप्रतिनिधि के बारे में बताएं, जो मेरी कालोनी की हर समस्याओं का समाधान करा पाए। वैसे यह सांसद, विधायक या निगम पार्षद में से किसी के लिए यह संभव है, अगर वैधानिक तरीके से कहा जाए तो यह किसी के लिए संभव नहीं है। केन्द्र सरकार के नियंत्रण वाला दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) वैधानिक कालोनी बनाकर उसे एक निश्चित समय के बाद दिल्ली नगर निगम को सौंप देता है। निगम कालोनी की सड़कें ठीक करने, साफ-सफाई आदि का काम तो करा सकती है लेकिन बिजली (दिल्ली विद्युत बोर्ड) और पानी (दिल्ली जल बोर्ड) दिल्ली सरकार के अधीन है। यह काम दिल्ली सरकार करेगी। मुख्य सड़कें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) यानी दिल्ली सरकार के अधीन ही है। कानून-व्यवस्था यानी दिल्ली पुलिस, केन्द्र सरकार के अधीन है। देश की राजधानी दिल्ली का वीआईपी इलाका यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद(एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी इलाका सीधे केन्द्र सरकार के अधीन है। इनके अलावा भी अनेक संस्थाएं स्वशासी हैं और उन पर दिल्ली की किसी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बावजूद इसके अलग-अलग समय में इन संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी कराने के लिए जन प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है। इन पर नियंत्रण केन्द्र सरकार से नियुक्त नौकरशाहों का ही है।

आजादी के बाद पूरी तरह से केन्द्र सरकार के अधीन आयुक्त प्रणाली लागू किया गया। 1952 में कम अधिकारों वाली विधानसभा बनी। उसे 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अनुपयोगी मानकर भंग करने की सिफारिश की। दिल्ली का विकास होने के साथ दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था बदलती गई। 1957 में दिल्ली नगर निगम बना और निगम के पास ही दिल्ली से जुड़े सर्वाधिक विभाग थे।1966 में महानगर परिषद बनी, उससे निगम के अधिकार कुछ कम हुए।

वर्ष 1911 में दिल्ली देश की राजधानी बनी। 1915 में यमुनापार के 65 गांव दिल्ली की सीमा में शामिल किए गए। तब से दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर की बनी हुई है, जबकि आबादी काफी बढ़ गई है। पिछले 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली-एनसीआर(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना) को करोड़ों रुपयों की लागत से बनी दो बड़ी सड़कों की सौगात दी और कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली को विकास मॉडल बनाएंगे। इससे पहले भी दिल्ली पर यातायात का दबाव घटाने के लिए मोदी सरकार ने ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस-वे, वेस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे बनवाया। दिल्ली मेट्रो रेल दिल्ली और एनसीआर में 416 किलोमीटर तक बन चुका है। इसके विस्तार का काम जारी है।

दिल्ली मेट्रो से हर रोज यात्रा करने वालों की औसत संख्या पचास लाख से ऊपर है। यह संख्या 70 लाख भी पार कर जाती है। दिल्ली-मेरठ नमो भारत रेल कोरिडोर के बाद दिल्ली- करनाल और दिल्ली- अरवल कोरिडोर बनने वाला है। इनसे यातायात सुगम होने के साथ-साथ इस इलाके का प्रदूषण भी कम होगा। कायदे में जिस रफ्तार से दिल्ली और एनसीआर की राजधानी की आबादी बढ़ रही है, उसमें इसे बचाने और बनाने के लिए नए फैसले लेने होंगे। दिल्ली की समस्या यह है कि उसका अपना ज्यादा कुछ नहीं है। मौसम भी पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। इतना ही नहीं दिल्ली अपनी जरूरतों को पूरा करने के संसाधनों के लिए भी दूसरे राज्यों पर निर्भर है। 1911 में दिल्ली देश की राजधानी बनी तब दिल्ली की आबादी करीब 2 लाख 38 हजार थी। 1991 में दोबारा विधानसभा बहाल होते समय करीब 94 लाख थी। अब आबादी करीब ढाई करोड़ है और एनसीआर की कुल आबादी की करीब साढ़े चार करोड़ से ज्यादा हो गई है।

ऐसा नहीं है कि बोर्ड की पूरी कवायत ही बेकार हो गई है। अगर दिल्ली सरकार इस पर अपनी केन्द्र सरकार से ठीक से पहल करवाए तो लक्ष्य हासिल हो पाएगा। एनसीआर के हर राज्य की जरूरत इस योजना पर ठोस काम कराने की है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत दिल्ली को है। इसलिए अगुवाई दिल्ली को करनी होगी। कायदे में तो दिल्ली की मौजूदा शासन व्यवस्था पर बहस होकर दिल्ली को पूरा (पूर्ण) राज्य बनाया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो नए कानून बनाकर एनसीआर योजना को ठीक से लागू किया जाए। निगम से केन्द्र तक भाजपा की सत्ता है। अभी जैसा अवसर उसे शायद फिर न मिले। उसका लाभ उसे उठाना चाहिए।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अलर्ट

तेजी से बढ़ता ई-सिगरेट का क्रेज... अपने हाथ से फेफड़ों और ब्रेन को डैमेज करते युवा

बाजार में नई चीजें युवाओं के बीच अक्सर लोकप्रिय बन जाती हैं। बीते कुछ वर्षों से सिगरेट पीने वाले लोगों के बीच ई-सिगरेट यानी वेपिंग का क्रेज बढ़ा है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर वेपिंग का इस्तेमाल करते दिखते हैं। यही वजह है कि युवाओं में भी वेपिंग का उपयोग बढ़ा है। ई सिगरेट अलग-अलग आकर्षक डिजाइन, अलग-अलग तरह के फ्लेवर में उपलब्ध होती है। वहीं डब्लूएचओ के आंकड़ों पर नजर डाले तो पता चलता है कि भारत में करीब 267 मिलियन वयस्क किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। जिसमें स्मोकिंग को भी शामिल किया जाता है। इसकी वजह से लंग्स डिजीज, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर रोग और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। इन रोगों के चलते भारत में हर साल करीब 1.35 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं।

ई-सिगरेट एक बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक विशेष लिक्विड को गर्म करके एरोसोल (वाष्प) बनाता है। इस लिक्विड में आमतौर पर निकोटीन, फ्लेवरिंग एजेंट और अन्य रासायनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। उपयोगकर्ता इस एरोसोल को सांस के जरिए अंदर लेता है, जिसे वेपिंग कहा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ई-सिगरेट में तंबाकू नहीं जलता, इसलिए यह सुरक्षित है। हालांकि, सीडीसी के अनुसार वेपिंग के दौरान निकलने वाले एरोसोल में कई हानिकारक रसायन और अल्ट्राफाइन कण मौजूद हो सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं।

लंग्स हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति ई-सिगरेट का उपयोग करता है तो उसके लंग्स में भाप के साथ में कई तरह के कैमिकल्स भी पहुंचते हैं। इनमें फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलिन और हैवी मेटल्स के सूक्ष्म कण शामिल हो सकते हैं। अमेरिकन लंग एसोसिएशन के अनुसार, ई-सिगरेट का एरोसोल फेफड़ों में सूजन पैदा कर सकता है और समय के साथ फेफड़ों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। कुछ मामलों में वेपिंग से जुड़ी गंभीर फेफड़ों की चोट भी हो सकती है, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होने की नौबत तक आ सकती है।

अमेरिकी सर्जन जनरल की रिपोर्ट के अनुसार, निकोटीन ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, याददाश्त और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, निकोटीन की लत भविष्य में अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग का जोखिम भी बढ़ा सकती है।

निशाना

उनकी यादों का सहारा ..!

धर्मराज देशराज

उनकी यादो क़ा सहारा चाहिए
वो नहीं ग़म उनका सारा चाहिए।
दर्दो-ग़म की हूँ नदी से बेख़बर
मेरी कश्ती को किनारा चाहिए।
यार मुझसे दूर मंज़िल है मेरी
साथ अब तेरा खुदारा चाहिए।
उम्र ग़ुज़री उनको न हम पा सके
जन्म यारब अब दुबारा चाहिए।
शहर,गलियाँ ये जहां भी छोड़ दूँ
सिर्फ इक तेरा इशारा चाहिए।
चाँद को पाना भी मुमकिन है यहाँ
सिर्फ किस्मत का सितारा चाहिए।
अश्क़ अपनी आँख के दे दो 'धरम'
हमको बस हिस्सा हमारा चाहिए।

टेक्नो अपडेट

देसी कंपनी का कमाल, रोज़ चार्जिंग की टेंशन खत्म करने वाला फोन लाने की तैयारी

भारत की देसी मोबाइल कंपनी लावा ने पिछले दिनों गोवा में 'इंसाइडर्स मीट' का आयोजन किया। इस इवेंट में मीडिया जगत के दिग्गज, टेक इन्फ्लुएंसर्स और लावा मोबाइल की लीडरशिप मौजूद रही। इवेंट का मकसद लावा की भविष्य की तकनीक और नए स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को पेश करना था। इस दौरान लावा की कोर लीडरशिप टीम ने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए और बताया कि कैसे LAVA AI की मदद से फोन चलाने के अनुभव को पूरी तरह से बदलने वाला है।

LAVA ने इस कार्यक्रम में अपनी उन पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज को पेश किया, जिनमें AI फीचर्स पर खास ध्यान दिया गया है। यहां Agni 4 का खासा जिक्र हुआ जो अपने Vayu AI के साथ आता है। मीडिया से बात करते हुए लावा इंटरनेशनल प्रोडक्ट हेड सुमित सिंह ने बताया कि फोन में ऑन डिवाइस AI देने से लागत काफी बढ़ जाती है और फोन महंगे हो सकते हैं। यही वजह है कि LAVA इस बात पर फोकस करता है कि उनके फोन में मौजूद AI डिवाइस को कंट्रोल करने लायक काम कर सके। इस मौके पर LAVA ब्लेज सीरीज को स्टाइल और बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहने वाले यूजर्स के लिए पेश किया गया। वहीं पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए स्मार्ट सीरीज और मजबूत परफॉर्मेंस के लिए बोल्ड सीरीज को सामने लाया गया, जो कम कीमत में बेहतरीन ऑप्शन उपलब्ध कराते हैं।

सुमित सिंह ने बताया कि कंपनी का फोकस लोगों तक किफायती 5G तकनीक पहुंचाने पर है, जिसके लिए शार्क सीरीज को लाया जा रहा है। कुछ समय पहले लॉन्च हुए Shark 2 5G स्मार्टफोन ने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि 15,000 रुपये से कम के बजट में इसमें 6000mAh की बेहद दमदार बैटरी दी गई है।

आने वाले स्मार्टफोन्स में सिलिकॉन कार्बन बैटरी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा और हाई-कैपिसिटी वाली बैटरी LAVA स्मार्टफोन्स में भी मिलेंगी। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि LAVA एक मिडबजट सेग्मेंट में भी नई स्मार्टफोन सीरीज लेकर आने वाली है। उन्होंने बताया कि यह सीरीज Agni सीरीज के फोन से सस्ती होगी और इस सीरीज में पेश किए जाने वाले पहले 5ज फोन की कीमत 20 से 25 हजार के बीच रखी जाएगी।

वायरल कंटेंट

बीमार छात्रा के लिए फरिश्ता बनीं वार्डन, नहीं मिली एंबुलेंस तो पीठ पर ले गईं अस्पताल

आज के समय में अक्सर लोग छोटी-सी जिम्मेदारी से भी पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने काम से यह साबित कर देते हैं कि सच्ची सेवा और इंसानियत आज भी जिंदा है। आंध्र प्रदेश से सामने आई एक ऐसी ही घटना इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। यहां एक स्कूल वार्डन ने बीमार छात्रा की जान बचाने के लिए जो किया, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना आंध्र प्रदेश के एक दूरदराज के आदिवासी इलाके की है। यहां एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर तक जल्द पहुंचाना जरूरी था, लेकिन इलाके में न एंबुलेंस उपलब्ध थी और न ही ऐसी सड़क, जहां वाहन आसानी से पहुंच सके. ऐसे मुश्किल समय में स्कूल की वार्डन ने बिना देर किए खुद जिम्मेदारी उठाई।

वार्डन ने छात्रा को अपनी पीठ पर बैठाया और अस्पताल की ओर पैदल निकल पड़ीं। यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। रास्ते में कच्चे रास्ते, पत्थर, पहाड़ी चढ़ाई और जंगल का इलाका था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. करीब 6 किलोमीटर तक लगातार पैदल चलकर वह छात्र को सुरक्षित अस्पताल तक ले गईं। उनके लिए सबसे अहम बात बच्चे का इलाज था, इसलिए उन्होंने अपनी थकान और कठिनाइयों की परवाह नहीं की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वार्डन सावधानी के साथ छात्रा को पीठ पर लेकर आगे बढ़ती दिखाई देती हैं। उनके चेहरे पर थकान जरूर नजर आती है, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं दिखती. यही वजह है कि लोग उन्हें समर्पण और मानवता की मिसाल बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग वार्डन को 'रियल हीरो' और 'प्रेरणादायक महिला' कहकर सम्मान दे रहे हैं। हालांकि, इस घटना ने एक गंभीर सवाल भी खड़ा किया है। आज भी देश के कई दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं और सड़क जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं की कमी बनी हुई है। अगर वहां समय पर एंबुलेंस और बेहतर सड़कें होतीं, तो शायद किसी को इस तरह कई किलोमीटर तक मरीज को पीठ पर उठाकर नहीं चलना पड़ता।

न्यूज विंडो

छिंदवाड़ा में पहचान छिपाकर काम कर रहा था हरभजन, पुलिस ने पकड़ा

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में पहचान छिपाकर शराब दुकान में काम करने और 5.46 लाख रुपये लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को दिल्ली और पंजाब में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी खुद को हरभजन बताकर पिछले तीन महीने से शराब दुकान में काम कर रहा था, जबकि उसका असली नाम साबिर अली है।

धार्मिक नगरी में पुराने स्टेट बैंक भवन पर कथित अवैध कब्जे का आरोप

अमरकंटक। धार्मिक एवं पर्यटन नगरी अमरकंटक, जो विशेष क्षेत्र के रूप में अधिसूचित है, वहां पुराने स्टेट बैंक भवन एवं उससे संबंधित भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भूमि का स्वामित्व पहले किसी अन्य व्यक्ति के नाम आवंटित था, बाद में यह एक ताम्रकार परिवार के नाम दर्ज हुई, लेकिन वर्तमान में एक अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है। आरोप है कि इस पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद राजस्व विभाग, नगर प्रशासन एवं अमरकंटक विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे सरकारी भूमि एवं अभिलेखों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

रेलवे जोन में मेडिकल क्लेम के नाम पर फर्जीवाड़ा, दो लिपिक सस्पेंड

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में मेडिकल क्लेम के नाम पर लाखों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। रेलवे कर्मचारियों पर इलाज के बिलों में हेराफेरी कर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप है। शुरुआती जांच में करीब 40 लाख रुपए के घोटाले की आशंका जताई गई है। मामले में दो लिपिकों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कई अन्य कर्मचारी और अधिकारी जांच के दायरे में हैं।

गृह निर्माण समिति की सदस्यता सूची पर 10 जुलाई तक आपत्ति आमंत्रित

जबलपुर। डॉ. बाबा साहब अंबेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर के संचालक मंडल के निर्वाचन के लिए सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने राज?य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहकारी निरीक्षक राजे-?द्र यादव ने प्रकाशित सदस्यता सूची पर 10 जुलाई तक आपत्तियां आमंत्रित की है। बाबा साहब अम्बेडकर गृह निर्माण समिति के संचालक मंडल के निर्वाचन के लिए सदस्यता सूची का प्रकाशन 3 जुलाई को किया गया था। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अनुसार सूची के संबंध में यदि किसी को आपत्ति है तो वह मय प्रमाण सहित लिखित में अपनी आपत्ति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कार्यालीन समय में कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाए जबलपुर या संस्था कार्यालय राइट टाउन जबलपुर में संस्था अध्यक्ष अथवा प्रबंधक को प्रस्तुत कर सकता है। प्रकाशित सदस्यता सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण संस्था कार्यालय में 11 जुलाई को किया जाएगा।

अधिकारियों को साइबर फ्रॉड के प्रति किया जागरूक, दिलाई शपथ

जबलपुर। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभा भवन में मध्य प्रदेश साइबर पुलिस द्वारा साइबर सिक्योर 2026 के तहत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार, अपर कलेक्टर नीता राठौर, रविशंकर राय, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत की मौजूदगी में संपन्न हुए इस प्रशिक्षण में अधिकारियों को साइबर खतरों के प्रति जागरूक किया गया। प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा साइबर अपराधों से बचाव के आधुनिक तरीकों और मोबाइल ऐप्स के सुरक्षित उपयोग पर व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते खतरों और उनसे बचने के उपायों के साथ-साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गई। प्रशिक्षण के समापन पर साइबर पुलिस द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई गई, ताकि वे डिजिटल युग में सुरक्षित रह सकें और साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकें।

तेंदूखेड़ा में भाजपा के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हजारों कार्यकर्ता

हमारा कार्यकर्ता देश, समाज, राष्ट्र के लिए कार्य करता हैं: धमेंद्र सिंह लोधी

तेंदूखेड़ा, दोपहर मेट्रो

नगर के आचार्य श्री विद्यासागर सागर दयोदय पशु सेवा केंद्र के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जिला कार्यकर्ता सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर के 24 मंडलों के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व जयंत मलैया ने कहा कि जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। वो चाहते तो अच्छी जिंदगी जीते, लेकिन उन्होनें अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित किया। स्वतंत्र पहली सरकार में उद्योग मंत्री रहे आज हम गर्व से कह सकते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा हैं धारा 370 समाप्त होने के चलते अब हमारा देश एक हैं। आज जो कार्यकर्ता सम्मलेन किया जा रहा हैं मेरे अनुसार जिले का सबसे बड़ा सम्मेलन हैं। जबसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हैं तब से निरंतर विकास कार्य जारी हैं। 12 वर्षो में सर्वोच्च विकास हुआ हैं। हमारा कार्यकर्ता ही सरकार का स्तंभ हैं जिनकी वजह से सरकार बनी हैं।

राज्यमंत्री धमेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी कट्टर देशभक्त, सुधारक, कर्मट कार्यकर्ता, विचारक जनसंघ के संस्थापक रहे। 1901 में कोलकाता में जन्म हुआ था। 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविघालय के कुलपति बने। स्वतंत्र भारत की सरकार में उघोग मंत्री रहते हुए कई कारखानों की स्थापना की। पंडित नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण उन्होनें अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और विपक्ष में आ गए। 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें। संसद में हमेशा राष्ट्रीय एकता की बात रखी। जम्मू कश्मीर के लिए कहा था कि जब देश एक हैं तो दो विधान, दो सरकार, दो झंडे इसका हमेशा विरोध किया। जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बनाने को लेकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। धारा 370 हटने के बाद पंडित मुखर्जी का सपना पूरा हो गया। हमारे प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाकर पंडित मुखर्जी के सपने को साकार किया हैं। आज हम गर्व से कह

सकते हैं कि उन्हीं की प्रेरणा से करोडो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता देश, समाज, राष्ट्रऊके लिए कार्य करता हैं। कांग्रेस को कार्यकर्ता बुलाने के गाडी पेट्रोल डीजल आदि की व्यवस्था करना पडती हैं। लेकिन हमारा कार्यकर्ता एक मैसेज मिलने पर ही दौडा चला आता हैं।

सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्य और वर्तमान की मोदी सरकार के कार्य एक समान हैं। पंडित जी ने हिंदुस्तान एयर क्राप्ट फैक्ट्र बेंगलौर, सिंधी उर्वरक कारखाना, दामोदर घाटी निगम, हीराकुंड बांध, भिलाई इस्पात कारखाना की नींव रखी थी। आज की सरकार में पंडित जी कार्यो की छवि देखने को मिलती हैं। पंडित जी ने पार्टी राष्ट्रभाव के निर्माण को लेकर बनाई थी। सच्चा कार्यकर्ता वहीं हैं जो धैर्यवान हो, घमंडी न हो, उत्साह से परिपूर्ण हो। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प हैं 2047 तक भारत विश्वगुरू बनें। राहुल सिंह ने नया नारा लगाया कि जहां जन्म हुए मुखर्जी, वो बंगाल हमारा हैं। इस दौरान बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के समय का कार्यकर्ताओं का दुख भी उन्होनें कार्यकर्ताओं को बताया।

सिद्धांत अपनाएं कार्यकर्ता

जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे ने भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतो को पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनाने के लिए कहा। कार्यक्रम में मंडलों से आएं वरिष्ट कार्यकर्ताओं, मीसबंदी का स्वागत किया गया एवं उपहार स्वरूप घडी भेंट की गई। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया, भावसिंह लोधी, पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह, पूर्व मंत्री दशरथ सिंह, पूर्व विधायक सोनाबाई, पीएल तंतुवाय, पथरिया से लोकेंद्र पटैल, प्रदेश महामंत्री गोपाल पटैल, कार्यक्रम प्रभारी अमित बजाज, राजेंद्र गुरू, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधी गौरव पटैल, उपाध्यक्ष मंजू धमेंद्र कटारे, नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश जैन सांसद प्रतिनिधि मूरत सिंह लोधी तारादेही मंडल अध्यक्ष डॉ मनोहर सिंह लोधी पूर्व मंडल अध्यक्ष गोविंद यादव नगर परिषद उपाध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद नामदेव चेतन जैन डॉ परम सिंह लोधी सरपंच संघ की अध्यक्ष नीतू साहू के अलावा सभी विभाग के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं दमोह जिले के 24 मंडलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

तीन हजार का इनामी अपहरणकर्ता गिरफ्तार नाबालिग बालिका को किया सकुशल बरामद

धार, दोपहर मेट्रो

जिले में नाबालिग बालक-बालिकाओं की सुरक्षित घर वापसी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन मुस्कान' को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना कानवन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए देपालपुर क्षेत्र से एक अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर उसके माता-पिता को सौंप दिया है। वहीं, पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित ?3,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना बीती 28 मार्च 2026 की है, जब एक अज्ञात बदमाश नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। 29 मार्च को पीड़िता के पिता लाखनसिंह चौहान निवासी कानवन ने थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 121/2026, धारा 137(2) बीएनएस (BNS) के तहत

मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

धार एसपी सचिन शर्मा के सख्त निर्देशों के बाद थाना प्रभारी कानवन निरीक्षक रविन्द्र कुमार बारिया ने अपनी टीम और सायबर सेल के साथ मिलकर जाल बिछाया। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, जिससे सटीक लोकेशन का पता चला। पुलिस टीम ने तत्काल इंदौर जिले के देपालपुर थाना क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी आकाश (25 वर्ष) को धरदबोचा और उसके कब्जे से बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने बालिका को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया। अपनी लाडली को सही-सलामत वापस पाकर परिजनों ने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर ?3,000/- का नगद इनाम घोषित किया गया था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। नाबालिग को सुरक्षित घर पहुंचाने में थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र बारिया, उपनिरीक्षक (उनि) कमल किशोर चौहान, आरक्षक नवीन कुमार राठौड़, आरक्षक भगवतीलाल और आरक्षक अजयपाल राठौर की मुख्य भूमिका रही। वहीं, तकनीकी मदद के लिए सायबर शाखा प्रभारी उनि प्रशांत गुंजाल, आरक्षक प्रशांतसिंह चौहान और आरक्षक शुभम शर्मा का कार्य भी बेहद सराहनीय रहा।

डिंडोरी में बारिश से कई इलाकों का संपर्क टूटा

डिंडोरी। डिंडोरी में मूसलाधार बारिश के कारण नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जिले में औसतन दो इंच वर्षा दर्ज की गई। तूड़ार नदी में बाढ़ आने से करंजिया ब्लॉक के कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है। नेशनल हाईवे के किनारे स्थित कुछ घरों में पानी घुसने से गृहस्थी का सामान खराब हो गया। करंजिया जनपद मुख्यालय से कुछ दूरी पर तूड़ार नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है। इसके कारण चौरा दादर सहित कई गांवों का जनपद मुख्यालय से संपर्क टूट गया है।

मुकेश कटारे महासचिव नियुक्त

नरसिंहपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी मुकेश कटारे को जिला कांग्रेस में महासचिव नियुक्त किया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता पटेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अनुमति एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति की सहमति से श्री कटारे को महासचिव नियुक्त किया है। विदित हो कि श्री कटारे पूर्व में भी अनेक पदों का दायित्व निभा चुके हैं। उनकी नियुक्ति से निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाभ मिलेगा।

हत्या के प्रयास का सनसनीखेज मामला 24 घंटे में सुलझा, दो गिरफ्तार

धार, दोपहर मेट्रो

पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों के खिलाफ मनावर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक विधि-विरुद्ध बालक (नाबालिग) को अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 05 जुलाई को फरियादी विकास (20 वर्ष) पिता मांगीलाल डावर, निवासी ग्राम कुराड़ाखाल ने थाना मनावर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विकास ने बताया कि 04 जुलाई की रात लगभग 11:00 बजे जब वह अपने साथियों के साथ कुराड़ाखाल फाटे के पास था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी रितेश, सुनील और एक अन्य नाबालिग वहां आए और गाली-गलौज करने लगे। विवाद बढ़ने पर आरोपी सुनील ने विकास के साथी पोसिया उर्फ गोपाल मेहड़ा के पेट में चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। बीच-बचाव करने आए आकाश नाम के युवक के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। गंभीर रूप से घायल गोपाल को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बड़वानी रेफर किया गया है।

फरियादी की शिकायत पर मनावर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हत्या का प्रयास की धारा में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन तथा एसडीओपी मनावर ब्रजेश मालवीय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और सूचना के आधार पर घेराबंदी कर 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को धरदबोचा। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए रितेश पिता स्व. नवलसिंह अम्लियार (उम्र 20 वर्ष), व सुनील पिता मगन चौहान (उम्र 21 वर्ष) तथा ही घटना में शामिल एक विधि-विरुद्ध बालक को भी पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। मुख्य आरोपी सुनील के पास से हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू जप्त कर लिया गया है।

मेट्रो एंकर

धार जिले के 7 वन परिक्षेत्रों में जनवरी से मई माह के बीच की गई हैं कार्रवाई

589 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि से हटाए कब्जे, अब रोपेंगे वहां पौधे

धार, दोपहर मेट्रो

वन भूमि संरक्षण एवं अतिक्रमण नियंत्रण अभियान के तहत जनवरी से मई 2026 जिले में कुल 589.63 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करा लिया है। वन विभाग के मैदानी अमले द्वारा सुनियोजित और शांतिपूर्ण तरीके से 7 वन परिक्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मुक्त कराई गई है। यह कार्रवाईयां वन मंडल अधिकारी विजयानंथम टीआर के मार्गदर्शन में विभाग ने जिला प्रशासन, पुलिस, ग्राम वन समिति और स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सहयोग से की हैं।

अतिक्रमण से मुक्त कराई गई इस भूमि का पुनर्वनीकरण किया जाएगा। वन विभाग इस पूरी

जमीन पर वर्षाकाल 2026 में सागौन का रोपण करेगा। इसके लिए धार वन मंडल ने वन

अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों को वैज्ञानिक पद्धति से रोपण, पौध संरक्षण और रखरखाव का विशेष प्रशिक्षण भी दिया है ताकि रोपण कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा हो सके।

अतिक्रमण करने वालों पर अब होगी सीधे एफआईआर

वन मंडल अधिकारी विजयानंथम टी.आर. ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वन भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति वन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन अपराध का मामला तो दर्ज होगा ही, साथ ही शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सीधे एफआईआर भी कराई जाएगी। वहीं वनभूमि पर कब्जा करने वालों पर नजर भी रखी जा रही है।

दस्तक अभियान 14 जुलाई से शुरू होगा

खंडवा। हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान एवं त्वरित उपचार व रैफर सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में दस्तक अभियान का प्रथम चरण 14 जुलाई से 31 अगस्त तक आयोजित किया जायेगा । मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने बताया कि डायरिया बीमारी से बढ़ती शिशु मृत्यु दर को संज्ञान में लेते हुए स्टॉप डायरिया कैम्पेन सह दस्तक अभियान डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखे अपना ध्यान की थीम पर आधारित है। जिसमें जन्म से पांच वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी एवं ओ.आर.एस. पैकेट, व जिंक टेबलेट का वितरण किया जायेगा।

नरसिंहपुर जिले के 171 शासकीय विद्यालय बने जल संरक्षण के प्रेरणा केंद्र

बूंद-बूंद सहेजने की बड़ी पहल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए

नरसिंहपुर। दोपहर मेट्रो

जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में नरसिंहपुर जिले के 171 शासकीय विद्यालयों ने अनुकरणीय पहल करते हुए अपने परिसरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए हैं। मध्यप्रदेश शासन के जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए गए इस कार्य ने शासकीय विद्यालयों को केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण की व्यवहारिक प्रयोगशाला और सामाजिक जागरूकता के प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

कलेक्टर रजनी सिंह के निर्देशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग द्वारा जल संरक्षण को लेकर व्यापक अभियान संचालित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुशवाहा ने बताया कि जिले के 171 शासकीय विद्यालयों में स्थापित रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वर्षा जल के वैज्ञानिक संरक्षण के साथ-साथ विद्यार्थियों में जल के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव विकसित कर रहे हैं।

स्कूल बने व्यवहारिक शिक्षा केंद

विद्यालयों में लगाए गए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ जल संरक्षण का व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान कर रहे हैं। छतों से एकत्रित वर्षा जल को संरक्षित कर भू-जल पुनर्भरण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में जल उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं इस जल का उपयोग विद्यालय परिसर की बागवानी, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक कार्यों में भी किया जा सकेगा।

'जल बचाओ' का संदेश पहुंचा घर-घर

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इमलिया-कमती एवं सांदीपनि विद्यालय, नरसिंहपुर सहित अनेक विद्यालयों में निबंध लेखन, पोस्टर निर्माण, जागरूकता रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर जल संरक्षण का संदेश समाज तक पहुंचाया। विद्यालयों में अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ने अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया। इस दौरान विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी जलसंरक्षण की शपथ दिलाई गई।

न्यूज विंडो

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नमो उपवन में रोपे पौधे

सागर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी एवं नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार के साथ नमो उपवन में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने इस मानसून सत्र में 25 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शहर की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं अन्य संस्थाओं को भी अभियान से जोड़ते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया गया है। इस अवसर पर विधायक जैन ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण केवल सरकार का नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। आज पर्यावरण संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है।

मंदिर में मवेशियों को रोकने के लिए लगाए गए कैटल ग्रिड बेअसर

अमरकंटक। पवित्र नगरी अमरकंटक स्थित नर्मदा मुख्य मंदिर में आवारा मवेशियों की समस्या लगातार बनी हुई है। मंदिर परिसर के विभिन्न प्रवेश मार्गों पर नगर पंचायत द्वारा लाखों रुपए की लागत से कैटल ग्रिड लगाए जाने के बावजूद मवेशी बेधड़क मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आए दिन असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नगर में भी आवारा मवेशियों के झुंड मुख्य मार्गों पर घूमते दिखाई देते हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक कई लोग इन मवेशियों की वजह से घायल भी हो चुके हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में फलाहारी आश्रम के समीप स्थित कांजी हाउस के रखरखाव पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों के अनुसार यहां साफ-सफाई, पीने के पानी और चारे जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। साथ ही आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में रखने की व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से नहीं की जा रही है। यही कारण है कि मवेशी पूरे नगर में खुलेआम घूम रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पंचायत न तो इन मवेशियों को पकड़कर किसी गौशाला में भेज रही है और न ही कांजी हाउस में रख रही है। इसके बजाय मंदिर परिसर के पांच प्रमुख मार्गों पर कैटल ग्रिड लगाकर समस्या के समाधान का दावा किया गया, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हो रही है। मवेशी बिना किसी बाधा के कैटल ग्रिड पार कर मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं।

स्वर्गीय अनिल यादव की जयंती पर पत्रकारों को किया सम्मानित

गंजबासौदा। नगर के वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद् स्व. अनिल यादव की 72वीं जयंती पर सोमवार को स्थानीय पत्रकार भवन में श्रद्धांजलि एवं पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों का सम्मान अनिल दाऊ फाउंडेशन की ओर से प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया।

स्व. अनिल यादव के छोटे भाई एवं नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने उनके जीवन, पत्रकारिता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उनसे जुड़े लोगों ने अपने संस्मरण साझा करते हुए उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली और समाज के प्रति समर्पण को याद किया। कार्यक्रम में स्व. अनिल यादव की स्मृति में प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण और समाज के वंचित वर्गों के मुद्दों पर उत्कृष्ट लेखन करने वाले पत्रकार या लेखक को सम्मानित करने की घोषणा की गई। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया तय करेगी। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल, गिरीश उपाध्याय और सतीश ऐलिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता श्याम बोहरे, क्षेत्रीय विधायक हरिसिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव, जनपद विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार, जनप्रतिनिधि और परिजन मौजूद रहे।

नर्मदापुरम में पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई

63 लीटर शराब, बिना नंबर की कार और रिवॉल्वर जब्त

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

थाना देहात पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 63 लीटर अवैध शराब, बिना नंबर की मारुति बलेनो कार, एक रिवॉल्वर (बिना मैगजीन) तथा एक खटकेदार चाकू जब्त कर आदतन आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जब्त मशरुका की कुल कीमत करीब 5.41 लाख रुपए बताई गई है।

पुलिस के अनुसार आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फेफरताल क्षेत्र में एक बिना नंबर की बलेनो कार में अवैध शराब ले जाई जा रही है। कार्रवाई के दौरान दीपक अहिरवार (34) निवासी महिमा नगर, नर्मदापुरम के कब्जे से 180 एमएल के 350 क्वार्टर (करीब 63 लीटर) अवैध शराब, एक बिना नंबर की बलेनो कार, एक रिवॉल्वर (बिना मैगजीन) और एक खटकेदार चाकू बरामद किए गए।

कई धाराओं में कार्रवाई

आबकारी विभाग ने अवैध हथियार मिलने पर आरोपी और जब्त सामग्री को थाना देहात पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने आबकारी विभाग की तहरीर पर अपराध क्रमांक 404/2026 दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला कायम कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

आरोपी आदतन बदमाश, पहले से 16 अपराध उस पर दर्ज

पुलिस के अनुसार आरोपी दीपक अहिरवार के खिलाफ थाना देहात और कोतवाली में मारपीट, लड़ाई-झगड़े और अवैध शराब से जुड़े 16 आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं।कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उषा मरावी, उपनिरीक्षक दिनेश मेहरा, सुखनंदन नर्रे, प्रवीण शर्मा, प्रधान आरक्षक नवीन दुबे, आरक्षक जितेंद्र सिंह राजपूत, सुनील साहू तथा आबकारी विभाग की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

नवागत पुलिस महानिरीक्षक शुक्ला ने किया पदभार ग्रहण

सागर। दोपहर मेट्रो

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी मिथिलेश कुमार शुक्ला ने पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन का पूर्ण प्रभार विधिवत ग्रहण कर लिया। उल्लेखनीय है कि मिथिलेश कुमार शुक्ला पिछले तीन माह से अधिक समय से पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम जोन के अपने नियमित दायित्वों के साथ-साथ पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। अब मध्य प्रदेश शासन के स्थानांतरण आदेश के तहत उन्होंने नर्मदापुरम से स्थानांतरित होकर सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियमित रूप से पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के उपरांत शुक्ला ने कहा कि सागर जोन में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम तथा आमजन के साथ पुलिस की संवेदनशील एवं जनोन्मुखी कार्यप्रणाली उनकी प्राथमिकता है।

छह माह बाद भी शिकायतों की जानकारी नदारद

अनूपपुर। दोपहर मेट्रो

अमरकंटक नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष बलीराम केवट द्वारा माई की बगिया के तत्कालीन प्रभारी मनोज कांत तिवारी पर लगाए गए आर्थिक अनियमितता एवं अवैध अतिक्रमण से जुड़े गंभीर आरोपों की शिकायत का अब तक क्या हुआ, इसकी जानकारी स्वयं शिकायतकर्ता को भी नहीं मिल सकी है। इससे जनसुनवाई में दिए गए आवेदनों के निस्तारण और उनकी मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनसुनवाई व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतों का समयबद्ध निराकरण है।

शिकायतकर्ता के अनुसार 24 दिसंबर 2024 को अनूपपुर कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में आवेदन देकर माई की बगिया के प्रभारी पर वित्तीय अनियमितताओं, अवैध अतिक्रमण तथा अन्य आरोपों की जांच की मांग की गई थी। इसके बाद भी कोई स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई। इसके पश्चात 11 जून 2025 को इसी विषय में शहडोल संभाग के आयुक्त को भी लिखित शिकायत दी गई। आवेदन में आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद संबंधित अधिकारी के विरुद्ध न तो जांच की स्थिति स्पष्ट की गई और न ही शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराई गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि दोनों स्तरों शिकायतें देने के बाद भी जांच की स्थिति, जांच अधिकारी और की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

108 फीट तिरंगा और जैन ध्वज के साथ निकली श्री नेमी गिरनार धर्म यात्रा, एकता का दिया संदेश

शोभायात्रा का जैन समाज ने किया भव्य स्वागत

गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो

विश्व जैन संगठन के तत्वावधान में आयोजित श्री नेमी गिरनार धर्म यात्रा का नगर में भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय श्री त्रिमूर्ति जिनालय से प्रारंभ हुई शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्री महावीर विहार पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

शोभायात्रा का प्रमुख आकर्षण 108 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) और 108 फीट लंबा पंचरंगा जैन ध्वज रहा। इसके साथ ही गिरनार पर्वत की आकर्षक प्रतिकृति श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। यात्रा में जैन समाज के बड़ी संख्या में धर्मावलंबियों के साथ अभय सेना के सदस्य एक समान वेशभूषा में शामिल हुए, जिससे अनुशासन और एकता का

संदेश देखने को मिला।

विश्व जैन संगठन के संस्थापक संजय जैन ने बताया कि यह धर्म यात्रा 25 जून को दिल्ली से प्रारंभ हुई है। देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से गुजरते हुए यह यात्रा 20 जुलाई को गुजरात के जूनागढ़ स्थित पवित्र श्री गिरनारजी सिद्ध क्षेत्र पहुंचेगी। लगभग 3,100 किलोमीटर की इस यात्रा का उद्देश्य जैन समाज को भगवान नेमीनाथ स्वामी की मोक्षस्थली गिरनार पहुंचकर मोक्ष कल्याणक महोत्सव में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि विश्व जैन संगठन के आह्वान पर देशभर से लाखों श्रद्धालु गिरनार पर्वत पहुंचकर भगवान नेमीनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक पर निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे। यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था का प्रसार ही नहीं, बल्कि शुद्ध आहार, शाकाहार, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक जागरूकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाना भी है।

मेट्रो एंकर स्थापित होगी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा, भूमि पूजन हुआ

नया बस स्टैंड - ब्लेजा पेट्रोल पंप मार्ग अब डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग

सिरोंज। दोपहर मेट्रो

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को अयोध्या बस्ती स्थित मुखर्जी उद्यान में उनकी प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उद्यान के समग्र विकास और नए बस स्टैंड से मंडी होते हुए ब्लेजा पेट्रोल पंप तक जाने वाले मार्ग का नाम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग रखने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई।

सभा में विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि क्षेत्र का विकास सकारात्मक सोच और जनहितकारी नीतियों के आधार पर होना

चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ही उनके लिए सर्वोपरि है और विकास कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने नशामुक्त समाज का संदेश देते हुए गुटखा और शराब से दूर रहने की अपील की।

विधायक शर्मा ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और सार्वजनिक योगदान का उल्लेख किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन साहू, उपाध्यक्ष मनोज साईनाथ, मंडल अध्यक्ष सीताराम कुशवाह, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सचिन शर्मा ने किया।

अतिक्रमण हटाने के निर्देश: कार्यक्रम के दौरान विधायक ने अधिकारियों को तालाब सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतोष चौरे ने कहा कि मुखर्जी उद्यान की परिकल्पना पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने की थी।

निबंध प्रतियोगिता और पौधारोपण

गंजबासौदा। मेरा युवा भारत विदिशा के तत्वावधान में सावित्री महिला मंडल के सहयोग से शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय बैहलोट में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन-अर्चन के साथ हुआ। इस अवसर पर मेरा युवा भारत विदिशा की लक्ष्मी शर्मा, सेवानिवृत्त महिला एवं बाल विकास खंड अधिकारी वंदना तिवारी, समाजसेविका रश्मि देशपांडे तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक काशीराम मालवीय ने डॉ. मुखर्जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान विद्यार्थियों को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद आयोजित निबंध प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में रितिका विश्वकर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्हें शील्ड एवं प्रमाण-पत्र दिया गया।

तीसरा टी-20 मुकाबला आज, सीरीज बचाने के लिए भारत की नई योजना

ट्रेंट ब्रिज में बदलेगी टीम इंडिया की रणनीति ! बिश्नोई की जगह खतरे में

नई दिल्ली, एजेंसी

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में पिछड़ने के बाद भारतीय टीम अब ट्रेंट ब्रिज में होने वाले तीसरे मुकाबले के लिए नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी में है। पहले मैच के बारिश में धुलने और दूसरे टी20 में हार के बाद यह मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम हो गया है। टीम प्रबंधन परिस्थितियों को देखते हुए प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर अतिरिक्त तेज गेंदबाज को मौका देने पर विचार कर रहा है। ऐसे में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की जगह खतरे में मानी जा रही है।

मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 में रवि बिश्नोई का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। उन्होंने चार ओवर में 60 रन खर्च किए और एक भी विकेट नहीं लिया। इसके अलावा तीन बैक-फुट नो-बॉल और एक महंगे ओवर ने भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा दीं। टीम प्रबंधन का मानना है कि ट्रेंट ब्रिज की पिच तेज गेंदबाजों के लिए अधिक मददगार हो सकती है, इसलिए अतिरिक्त पेसर के साथ उतरना बेहतर विकल्प रहेगा। यदि भारत तीन तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरता है तो युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को पदार्पण या वापसी का मौका मिल सकता है। नई गेंद से स्विंग कराने और अतिरिक्त उछाल हासिल करने की उनकी क्षमता इंग्लैंड की परिस्थितियों में टीम के लिए उपयोगी मानी जा रही है। हालांकि अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच में तीन विकेट लिए थे, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने उनके एक ओवर में 27 रन बनाकर मुकाबले का रुख बदल दिया था।

बल्लेबाजी में भी सुधार की जरूरत

भारतीय बल्लेबाजी भी अब तक पूरी तरह लय में नहीं दिखी है। कप्तान श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने उपयोगी पारियां खेलीं, लेकिन बीच के ओवरों में रन गति बनाए रखने में टीम को परेशानी हुई। इंग्लैंड के स्पिनरों और धीमी गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना सके। पिछले मुकाबले में भारत ने 190 रन जरूर बनाए, लेकिन यह स्कोर इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी के सामने पर्याप्त साबित नहीं हुआ। ट्रेंट ब्रिज की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर एक बार फिर सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और युवा वैभव सूर्यवंशी पर निगाहें रहेंगी। अभिषेक ने पिछले मैच में तेज शुरुआत करते हुए 24 गेंदों में 43 रन बनाए थे, जबकि वैभव अब डेब्यू के दबाव से बाहर निकलकर अधिक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करना चाहेंगे।

पुरानी हार भुलाकर बराबरी पर नजर

भारतीय स्पिन आक्रमण के प्रमुख गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती भी हालिया मुकाबलों में अपनी पुरानी धार नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे में गेंदबाजी इकाई पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। ट्रेंट ब्रिज भारत के लिए मिश्रित यादों वाला मैदान रहा है। वर्ष 2022 में सूर्यकुमार यादव के शानदार शतक के बावजूद टीम को यहां हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भारतीय टीम उस नतीजे को पीछे छोड़ते हुए सीरीज में बराबरी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

इंग्लैंड में जीत की डगर तलाशती टीम इंडिया

टी20 फॉर्मेट में लगातार 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया इन दिनों जीत के लिए जद्दोजहत कर रही है।पहले आयरलैंड के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।वहीं उसके बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी गंभीर सेना के हालात ठीक नहीं हैं।सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका,फिर दूसरी भिड़ंत में लगभग वही स्कोर हासिल करने के बाद टीम इंडिया को हार झेलना पड़ी।अब अगर वर्ल्ड चैंपियन को सीरीज में बने रहना है, तो उसे हर हाल में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में होने वाला आज का मैच जीतना ही होगा।हालांकि ऐसा अनुमान है कि मैच में बारिश का खलल भी पड़ सकता है।फिर भी अगर मैच होता है तो सवाल यह उठता है कि युवा विस्फोटक खिलाड़ियों की भरमार होने के बावजूद भी आखिरकार टीम इंडिया जीत का खाता कैसे खोले।अगर हम वर्ल्ड चैंपियन इस टीम की बात करें तो फिर बिना कोई मुकाबला हारे वर्ल्ड खिताब अपने नाम करने वाली टीम के 2 असल चैंपियन(बुमराह,हार्दिक) खिलाड़ी की गैरमौजूदगी से यह टीम मैदान पर लाचार दिख रही है।लेकिन जब बात विश्व स्तरीय 4 टीमों की काबलियत रखने वाली टीम की होती हो,तो फिर किसी भी खिलाड़ी के न होने की वजह टीम संयोजन का बिगड़ना मेरे हिसाब से कतई सही नहीं है।इंग्लैंड टीम ने आज के मुकाबले के लिए अपनी एकादश में कोई बदलाव नही किया है।मतलब इस मैच में भी अंग्रेज टीम 3 फिरकी के साथ ही मैदान में उतरेगी।पिछले मुकाबले में भले ही टीम इंडिया ने उनके ही फॉर्मूले को अपनाते हुए यही कॉम्बिनेशन मैच में उतारा था,लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने न तो पिच को भांपा व न ही मैदानी डाइमेंशन और हवा का रुख देखकर गेंदबाजी की।जिसका नतीजा मैच के रिजल्ट में साफ नजर आया।यहां तक कि भारतीय कप्तान की सूझबूझ का बेहद खराब नजरिया भी मैदान में देखने को मिला।दरअसल इंडियन पारी के मिडिल ओवर्स में जब करन की धीमी गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और स्कोर को 200 रनों के भीतर बांध दिया।इसके बाद भी श्रेयष और उनके गेंदबाजों को इंग्लैंड की पारी में गति के फायदे समझ न आये।एक ओर जहां फिरकी गेंदबाज तेज गति से लगातार गेंदबाजी करते रहे,जबकि करन जैसी गेंदबाजी में माहिर शिवम दुबे का गेंदबाजी से दूर रखना टीम की हार की सबसे बड़ी वजह रही।मतलब साफ है कि लगातार मिल रही हार में चूक सिर्फ मैनजेमेंट का संयोजन ही नहीं,कप्तान का मैदानी नजरिया भी टीम के लिए घातक साबित हो रहा है।टीम मैनेजमेंट का एकादश के संयोजन का फार्मूला क्या है यह बात अभी तक समझ से परे ही है।शायद अभी भी टीम मैनजेमेंट को यह एहसास ही नहीं हो रहा है कि टीम इंडिया सीरीज कहाँ खेल रही है।अब तक हुए मुकाबलों में टीम संयोजन के सबसे बड़े सवाल को हल करने के बाद मैनजेमेंट आज के मैच में भी एकादश का फेरबदल तय है।देखना यह है कि तीसरे मैच के विलेन माने जाने वाले विश्नोई की जगह गेंदबाज या फिर आलराउंडर को मौका दिया जाता है।सच कहें तो तमाम खेलप्रेमियों के लिए आज का सबसे बड़ा सस्पेंस यही होगा,लेकिन मेरी सोच अभी भी हटकर ही है।दरअसल टीम इंडिया के एकादश संयोजन में जो एक सेट फार्मूला अपनाया जा रहा है वह कितना कारगर हुआ वह तो साफ ही नजर आ रहा है।अब तक टीम में आलराउंडर के किरदार में टीम का हिस्सा बने अक्षर पटेल,शिवम दुबे,सुंदर और हर्षित राना का कप्तान ने मैच दर मैच मैदान में क्या प्रयोग किया यह सबसे बड़ा प्रश्नचिन्ह है।जबकि मैनजेमेंट का एकादश में शुद्ध गेंदबाज और आलराउंडर का लगातार अलटा-पलटी करने का तरीका यही जाहिर करता है कि वह पिच और मैदान का मिजाज ही नहीं पढ़ पा रहा है।अब जब मैनजेमेंट प्रयोग लगातार कर रहा हो और उसको शिकस्त झेलना पड़ रही हो तो फिर टीम इंडिया आखिर वह फार्मूला क्यों नहीं अपना रही जो उसकी असल ताकत रही है।हमेशा से अपने बल्लेबाजी म को मजबूत कर पार्ट टाइम गेंदबाज का इस्तेमाल कर बतौर 6वें गेंदबाज आजमाना टीम इंडिया के लिए कई बार निर्णायक साबित हुआ है।आखिरकार कब तक हम अक्षर पटेल,सुंदर और शिवम जैसे आलराउंडर के चमत्कार के आसरे जीत की आस रखेंगे,जबकि मैदान में कप्तान इनकी भूमिका बतौर आलराउंडर तय ही नहीं कर पाता है।वैसे भी जब टीम लगातार हार रही हो तो जीत की डगर खोजने के लिए मैनजेमेंट ओर कप्तान को कुछ अलग ही करना होगा।बस अब देखना यह है कि टीम इंडिया के जीत का फार्मूला कौनसी गली से निकल कर आता है, किसी भी विस्फोटक युवा की चमत्कारी पारी से या फिर मैनजेमेंट की कोई बदली हुई सोच से.... अब अगर दोनों ही मुकाम पर चैंपियन टीम फेल हुई तब तो सीरीज का हाथ से निकलना भी तय है।

आलोक गोस्वामी
खेल विश्लेषक

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 में बड़ा उलटफेर

आखिरी मिनट में टूटा रोनाल्डो का सपना मेरिनो के एक गोल से पुर्तगाल हुआ बाहर

डलास, एजेंसी

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 मुकाबले में स्पेन ने आखिरी पलों में गोल दागकर पुर्तगाल को 0-1 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल मिकेल मेरिनो ने इंजरी टाइम (90+1वें मिनट) में किया। इस जीत के साथ स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया।

मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने कई अच्छे मौके बनाए, लेकिन कोई भी उन्हें गोल में नहीं बदल सका। स्पेन के लिए मिकेल ओयारजाबाल के पास बढ़त दिलाने का बेहतरीन मौका था, लेकिन उनका शॉट लक्ष्य से बाहर चला गया। वहीं, गोलकीपर डियोगो कोस्टा ने एलेक्स बेना के शानदार कर्लिंग शॉट को बचाकर पुर्तगाल को शुरुआती झटका लगने से बचाया।

रोनाल्डो और नूनो मेंडेस ने भी किया संघर्ष

पुर्तगाल ने भी लगातार स्पेन की रक्षा पंक्ति पर दबाव बनाया। कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कुछ अच्छे हमले किए, जबकि नूनो मेंडेस का डिफ्लेक्टेड शॉट क्रॉसबार से टकराकर लौट आया। इसके बावजूद पुर्तगाल पूरे मैच में गोल करने में नाकाम रही।

इंजरी टाइम में मेरिनो बने स्पेन के हीरो

दूसरे हाफ में दोनों टीमें सतर्क रहीं और मुकाबला गोलरहित आगे बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था कि मैच अतिरिक्त समय में जाएगा, लेकिन 90+1वें मिनट में स्पेन के दो सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों ने मैच का फैसला कर दिया। फेरान टोरेस ने बेहतरीन पास दिया, जिस पर मिकेल मेरिनो ने शानदार फिनिश करते हुए स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी। यही गोल अंत में निर्णायक साबित हुआ।

पहले हाफ में दोनों टीमों को नहीं मिली सफलता

रोनाल्डो का विश्व कप करियर समाप्त

इस हार के साथ 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप 2026 अभियान समाप्त हो गया। मैच से पहले ही रोनाल्डो ने कहा था कि यह उनके करियर का आखिरी फीफा विश्व कप होगा। उन्होंने अपने विश्व कप करियर में 27 मैचों में 11 गोल किए और लगातार छह अलग-अलग विश्व कप संस्करणों में गोल करने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने का रिकॉर्ड बनाया।

स्पेन ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

इस जीत के साथ स्पेन ने विश्व कप इतिहास में लगातार छह मैचों में क्लीन शीट (जब कोई टीम पूरे मैच या निर्धारित समय में विरोधी टीम को एक भी गोल करने नहीं देती है) रखने वाली पहली टीम बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब स्पेन क्वार्टर फाइनल में अमेरिका और बेल्जियम के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से भिड़ेगा।

मनोरंजन | **बॉलीवुड का कोना**

अंगूरी भाभी का लॉकअप में आतंक, गोविंदा की पत्नी से भिड़ीं, गुस्साई सुनीता ने की बोलती बंद

एकता कपूर के रियलिटी शो लॉक अप में इस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. टेंशन के माहौल के बीच एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे की वाइल्ड कार्ड एंट्री ने लॉक अप में तहलका मचा दिया है. शिल्पा ने शो में एंट्री करते ही हर किसी से पंगे लेने शुरू कर दिए. राम कपूर के बाद शिल्पा ने सुनीता आहूजा को उकसाने की कोशिश की. लेकिन सुनीता ने अपने जवाब से शिल्पा की बोलती बंद कर दी.

शिल्पा शिंदे शो में सुनीता आहूजा पर उनकी शादी को लेकर तंज कसती नजर आईं. शिल्पा ने सुनीता को ताने मारते हुए कहा-हम तो गोविंदा के फैन हैं. आप ऐसे कैसे कर सकती हो? आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? आपको पता भी है आपने क्या फैसला लिया है? शिल्पा के तानों से परेशान सुनीता भी चुप नहीं रहीं. उन्होंने बेबाकी से शिल्पा को लताड़ लगाई. सुनीता गुस्से से शिल्पा से बोलीं- जब तुम्हारे ऊपर गुजरेगा तुम्हें तब पता चलेगा. ज्यादा बक... मत करो. सुनीता का बेबाक अंदाज फैंस को काफी पसंद आया. फैंस का कहना है कि सिर्फ सुनीता ही शिल्पा शिंदे को चुप करा सकती हैं.

फूट-फूटकर रोईं सुनीता

इसके अलावा शो में सुनीता का इमोशनल ब्रेकडाउन भी देखने को मिला. खाना न मिलने की वजह से सुनीता मेकर्स से नाराज दिखीं. उन्होंने रोते हुए शो के मेकर्स को खरी-खोटी सुनाई. सुनीता शो में काफी गालियां देती हुई भी नजर आईं. सुनीता गुस्से से बोलीं- हमें खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है. मेरे सारे बच्चे यहां भूखे हैं. मुझे चीची मना कर रहा था कि मत जा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी. जब भी मैं उसकी बात नहीं मानती तो पछताती हूं. सुनीता ने शो छोड़ने की धमकी भी दी. वो फूट-फूटकर रो पड़ीं. फिर रितेश देशमुख ने उन्हें संभाला और उनके आंसू पोंछकर उन्हें चुप कराया. लॉक अप में इंटेंस ड्रामा देखने को मिल रहा है. इसलिए आप भी कोई एपिसोड मिस न करें.

तुम अभी भी मोटी हो, शिल्पा शिरोडकर ने बताया क्यों छिन गया था फेमस गाना छैया छैया

मुंबई । 90 के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड के सबसे मशहूर गानों में से एक %छैया छैया% में काम न कर पाने को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। हाल ही में डांस रियलिटी शो %इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5% में नजर आईं एक्ट्रेस ने उस घटना को याद करते हुए बताया कि इस मशहूर गाने की कोरियोग्राफर फराह खान को लगता था कि वह इस गाने के लिए मोटी हैं। शो के होस्ट हर्ष लिम्बाचिया ने पूछा, ÷शिल्पा मैम, मुझे एक बात पता चली है। मशहूर गाना %छैया छैया%, असल में शुरू में आपको ही करना था।÷

उस घटना को याद करते हुए शिल्पा ने कहा, ÷हां, असल में फराह गाना लेकर आई थीं और उन्होंने कहा था, %यह गाना है लेकिन मैं तुम्हें 15 दिन दे रही हूं। अपना वजन कम करो।% तो मैंने 15 दिन तक उबली हुई सब्ज़ियां खाईं लेकिन भले ही मेरा वजन कम हुआ हो, पर फराह के हिसाब से वह काफी नहीं था। इसलिए वह वापस आईं और कहा, %सॉरी, लेकिन तुम अभी भी मोटी हो। हम तुम्हें इस गाने के लिए नहीं ले सकते% और फिर यह गाना मलाइका अरोड़ा के साथ हुआ। मेरा मतलब है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं मोटी थी, इसलिए मुझे गाना नहीं मिला और फराह कहती हैं कि मैं 100 किलो की थी। मैं 100 किलो की नहीं थी।÷

इस खुलासे ने सेट पर मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। बातचीत को थोड़ा हल्का-फुल्का बनाते हुए शिल्पा ने जज गीता कपूर की ओर देखा और कहा कि उन्होंने खुद वह घटना देखी थी। गीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ÷मैं असिस्टेंट थी।÷

यूरोपीय यूनियन का चीन को बड़ा झटका, सस्ते सामानों पर लगाई 3 यूरो की एक समान कस्टम ड्यूटी

मेट्रो बाजार

नई दिल्ली । यूरोपीय यूनियन (ईयू) ने सस्ते सामानों पर 3 यूरो की एक समान कस्टम ड्यूटी लगाकर चीन को बड़ा झटका दिया है। इस कदम के जरिए ईयू की कोशिश चीन जैसे देशों से हो रहे आयात को संतुलित करना और पारदर्शिता को बढ़ाना है। यह जानकारी ग्रीक सिटी टाइम्स के आर्टिकल में दी गई।

ईयू की एएडीई (पब्लिक रेवेन्यू के लिए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी) ने घोषणा की है कि 150 यूरो तक की कम कीमत वाले आयातित सामान पर कस्टम ड्यूटी से मिलने वाली छूट खत्म की जा रही है, जिसका सीधा असर विदेश से ऑनलाइन शॉपिंग पर पड़ेगा। अगले बुधवार से, ग्रीस और यूरोपियन यूनियन में कस्टम्स पर, बी2सी डिस्टेंस सेल्स के लिए हर डिक्लेरेशन लाइन पर 3 यूरो की एक खास एक समान शुल्क लगाया जाएगा।

इस उपाय का असर पहले से ही लोगों की दिख रहा है, क्योंकि कई ग्राहक कुल लागत में भारी बढ़ोतरी देखकर अपनी खरीदारी रद्द कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, तीन अलग-अलग उत्पादों पर लगने वाली एक समान शुल्क के कारण 6 यूरो के ऑर्डर पर 9 यूरो का अतिरिक्त खर्च जुड़ सकता है। इस तरह कुल खर्च 15 यूरो तक पहुंच जाता है, जिससे चीन या अमेरिका जैसे देशों से खरीदारी करना पहले के मुकाबले कम आकर्षक हो गया है। यह नई स्पेशल ड्यूटी अस्थाई है और एक जुलाई, 2028 तक लागू रहेगी। उसके बाद सभी ई-कॉमर्स गुड्स पर स्टैंडर्ड टैरिफ रेट के मुताबिक ही

दक्षिण कोरियाई तकनीक का इस्तेमाल करके गुजरात बनाएगा रबर डैम

छोटा उदयपुर/तापी । गुजरात, दक्षिण कोरिया की रबर ब्लैडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने पहले दो एयर-फिल्ड रबर डैम बनाने जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स से छोटा उदयपुर और तापी जिलों में सिंचाई, ग्राउंडवाटर रिचार्ज और बाढ़ प्रबंधन में सुधार होने की उम्मीद है। अभी बन रहे दो बांधों में छोटा उदयपुर जिले के बोदेली तालुका में हेरन नदी पर बना राजवासना रबर बांध और तापी जिले के डोलवन तालुका में अंबिका नदी पर बना पाठकवाड़ी रबर बांध शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स में कुल मिलाकर 162 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स दूर-दराज के इलाकों में सिंचाई और पानी की सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन कैंपेन को भी सपोर्ट करते हैं। राजवासना रबर डैम का निर्माण 82.97 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 30 महीने की निर्माण अवधि में सितंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस डैम में हेरन नदी पर 180 मीटर लंबा और 3.5 मीटर ऊंचा हवा भरने वाला रबर ब्लैडर लगाया जाएगा।

सरकार के अनुसार, इस टेक्नोलॉजी से मौजूदा वियर की पानी जमा करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी, जिससे इसमें 3.5 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी जमा किया जा सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से 25 गांवों के किसानों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि इससे 3,420 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हो सकेगी। पानी का स्टोरेज बढ़ने से ग्राउंडवाटर लेवल में भी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे आस-पास के इलाकों में सिंचाई और पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

हिमाचल : ये बर्फ नहीं, सेब बागवानी की तस्वीर है...

शिमला और आसपास के सेब बहुल इलाकों में इन दिनों पहाड़ बर्फ से नहीं, बल्कि सफेद एंटी-हेल नेट से ढके नजर आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती ओलावृष्टि से फसल बचाने के लिए बागवान बड़े पैमाने पर इन प्लास्टिक जालियों का सहारा ले रहे हैं। इससे हिमाचल की करीब 5,000 करोड़ रुपए की सेब अर्थव्यवस्था को राहत तो मिल रही है, लेकिन प्राकृतिक हिमालयी सौंदर्य और पर्यावरण पर इसका असर भी साफ दिखने लगा है। किसानों का कहना है कि बिना हेल नेट के अब सेब उत्पादन जोखिम भरा हो गया है, हालांकि इन्हें खरीदने, लगाने और संभालने में भारी खर्च व श्रम लगता है।

करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगी सुनवाई

नई दिल्ली. एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने द्रमुक द्वारा दायर एक याचिका को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु सरकार के मंत्री पिछले वर्ष के करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच में गवाहों

को 'सक्रिय रूप से प्रभावित' कर रहे हैं। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला और शील नागू की एक आंशिक कार्य दिवस बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी की याचिका पर मंगलवार को मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति दी थी, जो द्रमुक सचिव आरएस भारती की ओर से पेश हुए थे और उन्होंने तात्कालिक सुनवाई की मांग की। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, राज्य मंत्री आदव अरजुना और अन्य आरोपितों को मामले पर सार्वजनिक बयान देने से रोका जाए और सीबीआइ जांच के दौरान पीड़ितों के परिवारों के साथ उनके संपर्क को नियंत्रित किया जाए।

भारत की अर्थव्यवस्था को मिल सकती है बड़ी राहत

26 साल की सबसे बड़ी कटौती सऊदी ने सस्ता किया कच्चा तेल

रियाद, एजेंसी

दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातक देश सऊदी अरब ने अगस्त के लिए अरब लाइट क्रूड की कीमत में 26 वर्षों की सबसे बड़ी कटौती करते हुए एशियाई ग्राहकों के लिए इसे ओमान-दुबई बेंचमार्क से 1.50 डॉलर प्रति बैरल कम कर दिया है। इससे पहले जुलाई में भी कीमतों में भारी कमी की गई थी। साथ ही ओपेक+ देशों ने अगस्त से प्रतिदिन 1.88 लाख बैरल अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ेगी। अधिक आपूर्ति के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 71.7 डॉलर प्रति बैरल तक आ गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ भारत जैसे देशों को मिल सकता है, जो अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करते हैं। सस्ता कच्चा तेल मिलने से रिफाइनरियों की लागत घटेगी, तेल कंपनियों पर वित्तीय दबाव कम होगा और सरकार की एलपीजी सब्सिडी का बोझ भी घट सकता है। इससे परिवहन, उद्योग और बिजली उत्पादन की लागत कम होने के साथ महंगाई पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।

सऊदी ने क्यों घटाईं कीमतें

वैश्विक तेल बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक आपूर्ति के बीच सऊदी अरब ने यह बड़ा कदम उठाया है। होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही सामान्य होने, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आपूर्ति बहाल करने और ओपेक+ देशों के उत्पादन बढ़ाने से बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ गई है। ऐसे में सऊदी अरब ने एशियाई ग्राहकों को आकर्षित करने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए कीमतों में रिकॉर्ड कटौती की है। इसका उद्देश्य अन्य तेल उत्पादक देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बने रहना और निर्यात को मजबूत करना है। भारत अपनी तेल जरूरतों का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, इसलिए कच्चा तेल सस्ता होने से आयात बिल कम हो सकता है। इससे रिफाइनरियों और तेल विपणन कंपनियों की लागत घटेगी तथा एलपीजी पर होने वाला नुकसान कम होने की संभावना है। सरकार की सब्सिडी का बोझ भी घट सकता है। यदि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में नरमी बनी रहती है तो परिवहन, बिजली उत्पादन और उद्योगों की लागत कम होगी, जिससे महंगाई पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। हालांकि पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में राहत मिलना सरकार की कर नीति और तेल कंपनियों के निर्णय पर निर्भर करेगा।

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हादसा

टायर फटने से चकनाचूर हुई ब्रेजा, तीन युवकों की मौत

मेरठ, एजेंसी

मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सकौती ओवरब्रिज से पहले तेज रफ्तार ब्रेजा कार का अगला टायर फटने से वाहन अनियंत्रित हो गया। कार कई पलटी खाने के बाद सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे चारों युवकों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। दो अन्य गंभीर घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ दिया। चौथे घायल का उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त ब्रेजा कार पर दिल्ली का पंजीकरण अंकित है। प्रारंभिक आशंका है कि सभी युवक दिल्ली के रहने वाले हो सकते हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। मौके से तीन मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, लेकिन सभी में सुरक्षा ताला लगा होने के कारण उनसे कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस वाहन के पंजीकरण के आधार पर मृतकों और घायल की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि चारों युवक किस स्थान से आ रहे थे और उनका गंतव्य क्या था। हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

आपसी झगड़े में माता-पिता ने की 11 महीने के मासूम की हत्या, फिर रची झूठी कहानी

बेंगलुरु, एजेंसी

बेंगलुरु पुलिस ने एक 11 महीने की बच्ची की हत्या के आरोप में उसके माता-पिता को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि आरोपियों ने अपनी ही बच्ची की हत्या करने के बाद इसे एक हादसे का रूप देने की कोशिश की थी। पुलिस के अनुसार, बच्ची के पिता शेकप्पा ने शुरुआत में पुलिस के पास जाकर दावा किया था कि उसकी पत्नी विजयलक्ष्मी स्तनपान कराते समय सो गई थी और इसी दौरान बच्ची बिस्तर से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले को शुरुआत में पुलिस ने अप्राकृतिक मौत के तौर पर दर्ज किया था।

यह घटना 9 जून को पूर्वी बेंगलुरु के अवालाहल्ली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितागनूर गांव में हुई थी। शेकप्पा ने अपनी शिकायत में बताया था कि बच्ची को तुरंत ईस्ट पॉइंट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी आधार पर अधिकारियों ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। 22 जून को प्राप्त हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके बाद की जांच ने माता-पिता की गढ़ी हुई कहानी की पोल खोल दी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मासूम की मौत अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव और कई अंदरूनी चोटों के कारण सांस लेने में हुई तकलीफ से हुई है।

होर्मुज से गुजर रहे दो जहाजों पर ईरान ने दागीं मिसाइलें

मस्कट, एजेंसी

सोमवार रात खाड़ी क्षेत्र के बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कम से कम दो मिसाइलें दागीं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में यह बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ईरान की मिसाइलों के हमले में दो व्यापारिक जहाजों को काफी गंभीर नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि इस हमले में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है और न ही कोई घायल हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल

कमांड ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बता दें कि ब्रिटेन की समुद्री व्यापार एजेंसी (यूकेएमटीओ) ने मंगलवार सुबह जानकारी दी कि ओमान के लीमा इलाके से लगभग 15 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर जा रहे एक तेल टैंकर पर अज्ञात गोला आकर गिरा। यह हमला जहाज के बाईं (पोर्ट) तरफ हुआ, जिससे उसमें आग लग गई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना में भी कोई हताहत नहीं हुआ है और न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की कोई खबर है। ये हमले तब हुए जब होर्मुज़ जलडमरूमध्य में हमले रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुआ एक हफ्ते का समझौता खत्म हो गया था। यह अस्थायी विराम ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के छह दिन तक चले राजकीय अंतिम संस्कार समारोह के दौरान हुआ था। सोमवार को उनके शव को तेहरान से पवित्र शहर कोम ले जाया गया, जिसके लिए एक विशाल अंतिम संस्कार जुलूस निकाला गया जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। एक्सियोस ने रिपोर्ट दी है कि अब वाशिंगटन ईरानी ठिकानों पर जवाबी हमले करने पर विचार कर सकता है।

दोपहर मेट्रो | **डीआरडीओ-एआरडीई और स्टार्टअप द्वीपा डिफेंस की बड़ी उपलब्धि**

स्वदेशी राइफल...सिर्फ 100 दिनों में तैयार हुई 'उग्रम'

पटियाला, एजेंसी

भारत ने रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद स्थित रक्षा स्टार्टअप द्वीपा डिफेंस ने डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एआरडीई) के सहयोग से केवल 100 दिनों में 'उग्रम' नामक स्वदेशी बैटल राइफल विकसित कर रिकॉर्ड बनाया है। यह 7.62x51 मिमी कैलिबर की आधुनिक राइफल है, जिसे इंसास राइफल से अधिक घातक और प्रभावी माना जा रहा है। उग्रम 500 मीटर तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है और इसमें आधुनिक गैस-ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम लगाया गया है। इसका वजन चार किलोग्राम से कम रखा गया है, जिससे सैनिकों के लिए इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना आसान होगा। कंपनी के अनुसार, राइफल ने सेना के जीएसक्यूआर, विभिन्न मौसमों में फील्ड ट्रायल और गृह मंत्रालय के सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसके बाद सीआरपीएफ, एनएसजी और आईटीबीपी जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों में इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2018 में स्थापित द्वीपा डिफेंस अब तक 100 से अधिक स्वदेशी हथियार प्रणालियां विकसित कर चुकी है। कंपनी का मानना है कि उग्रम के बड़े पैमाने पर उपयोग से छोटे हथियारों के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी और 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को नई मजबूती मिलेगी।

स्टार्टअप से आत्मनिर्भर भारत को मजबूती

2018 में स्थापित द्वीपा डिफेंस को 2021 में हथियार निर्माण का लाइसेंस मिला था। कंपनी अब तक 100 से अधिक स्वदेशी हथियार प्रणालियां और उनके विभिन्न वैरिएंट विकसित कर चुकी है। उग्रम के अलावा कंपनी यू-19 सब-मशीन गन, यू-45 असॉल्ट राइफल, अल्ट्रा-लाइट मशीन गन, कार्बाइन, लाइट मशीन गन और एंटी-ड्रोन सिस्टम भी तैयार कर रही है। कंपनी का उद्देश्य भारतीय सुरक्षा बलों को विश्वस्तरीय स्वदेशी हथियार उपलब्ध कराना और रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को लगातार कम करना है।

भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखा

उग्रम 7.62x51 मिमी कैलिबर की आधुनिक बैटल राइफल है, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह 500 मीटर तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसमें गैस-ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम लगाया गया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और फायरिंग क्षमता बढ़ती है। राइफल का वजन चार किलोग्राम से कम है, जिससे सैनिकों को लंबी तैनाती के दौरान सुविधा मिलती है। कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी इसके प्रदर्शन को सफल परीक्षणों के दौरान प्रमाणित किया गया है। डीआरडीओ के एआरडीई और द्वीपा डिफेंस ने केवल 100 दिनों में उग्रम का विकास कर रक्षा क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। राइफल ने सेना के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट (जीएसक्यूआर) ट्रायल, सभी मौसमों में बड़े पैमाने पर फील्ड टेस्ट और गृह मंत्रालय के बोर्ड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन सफल परीक्षणों के बाद सीआरपीएफ, एनएसजी और आईटीबीपी सहित कई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे जल्द ही यह सुरक्षा बलों का हिस्सा बन सकती है।

करण टेकर के नाम पर साइबर ठगी अभिनेता ने दर्ज कराई एफआईआर

नई दिल्ली, एजेंसी

टीवी और ओटीटी अभिनेता करण टेकर के नाम का दुरुपयोग कर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। अभिनेता ने खुद को उनका मैनेजर बताकर लोगों से संपर्क करने और पैसों के बदले मुलाकात कराने का झांसा देने वाले शख्स के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामला तब सामने आया, जब कुछ लोगों ने करण को उस कथित मैनेजर के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट भेजे। जांच में पता चला कि आरोपी खुद को अभिनेता का आधिकारिक प्रतिनिधि बताकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा था। करण टेकर ने बताया कि सही समय पर जानकारी मिलने से बड़ी ठगी होने से बच गई। उन्होंने कहा कि फर्जी व्यक्ति अनजान लोगों से संपर्क कर खुद को उनका मैनेजर बता रहा था और पैसे लेकर मुलाकात कराने का दावा कर रहा था। अभिनेता ने स्पष्ट

किया कि उनका उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने मामले की शिकायत साइबर क्राइम अधिकारियों को सौंप दी है। फैंस को सतर्क करने के लिए करण ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट साझा की। उन्होंने उन मोबाइल नंबरों की जानकारी दी, जिनका इस्तेमाल कथित ठग कर रहा था, और लोगों से अपील की कि ऐसे नंबरों से कॉल या संदेश मिलने पर किसी भी तरह का भुगतान न करें। उन्होंने लोगों से इन नंबरों को ब्लॉक और रिपोर्ट करने का आग्रह किया। बता दें कि करण टेकर 'स्पेशल ऑप्स', 'खाकीः द बिहार चैप्टर' और हालिया हॉरर सीरीज 'भय' में अपने दमदार अभिनय के लिए चर्चा में रहे हैं।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रसलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया स्थानीय संपादक अनिल शर्मा*** आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564